span style='mso-bidi-font-weight:bold'>

Title : Further discussion on the resolution regarding steps to ensure availability of drinking water in the country moved by Shri Satpal Maharaj on the 10th July, 2009.

MADAM SPEAKER: The House will now take up item No. 16, the Private Members' Business. Shri Satpal Maharaj.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछली बार 10 जुलाई को मैं पेयजल की समस्या पर बोल रहा था। हमारे देश में यह परम्परा रही है कि जब छोटे अपने पुरखों के, बड़ों के पैर छूते हैं, तो उन्हें आयुष्मान भव का आशीर्वाद प्राप्त होता था।

15.39 hrs. (Mr. Deputy Speaker *in the Chair)*

परन्तु जब पेयजल प्रदूषित होगा, पीने का जल दूषित होगा, तो कैसे वे लंबी आयु से जी सकेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि फ्लोराइड, आर्सेनिक और सिलेनियम जैसे प्रदूषित तत्व पानी का प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। भारत में साढ़े तीन सौ करोड़ आदमी इससे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जब वायुमंडल में प्रदूषण हो जाता है तब आक्सीजन कार्बन डाइआक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी शांत रहिये।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): गाड़ियों का धुंआ जीना दूभर बना देता है जैसे दिल्ली में कुछ साल पहले आंखों में जलन होना शुरू हो जाती थी। परन्तु हमारी दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने सीएनजी को लाकर एक बहुत बड़ा उपकार किया। इससे यहां का प्रदूषण कम हो गया।

इससे दिल्ली वालों को राहत मिली। मैं इस अच्छे कार्य के लिए शीला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वायुमंडल में जो प्रदूषण बढ़ जाता है, प्रकृति फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से उसका शुद्धिकरण कर देती है। हमारे जंगलों में, ग्रीनरी में जो हरा पदार्थ होता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, वह क्लोरोफिल कॉर्बन डाई आक्साइड और कॉर्बन मोनो आक्साइड को आक्सीजन में बदल देता है। प्रकृति में शुद्धिकरण के लिए यह रचना है, परन्तु धरती के अन्दर का जो जल केमिकल्स के जाने से प्रदूषित हो जाता है, वह फिल्टर नहीं हो पाता है। इससे हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे ऋषि-मुनियों का यह आशीर्वाद रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भागभावेत्। हमारे ऋषियों ने भारत के लिए, विश्व के लिए यह प्रार्थना की कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, लेकिन हम निरोग तभी होंगे जब हमें शुद्ध जल प्राप्त होगा। आज देश के कोने-कोने में शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो रहा है। जो धनवान लोग हैं, वे 10-15 रूपए की बिसलेरी की बोतल खरीद सकते हैं, लेकिन गांव में रहने वाला किसान, जो अन्नदाता है, धरती को जोतकर अन्न पैदा करता है, जो अपना पसीना बहाकर अन्न पैदा करता है, वह 10-15 रूपए की बिसलेरी की बोतल खरीदकर नहीं पी सकता है। उसे उसी कुएं का पानी पीना पड़ता है जिसमें मेंढक तैरते हैं, जर्म्स तैरते हैं, उसको धरती का मटमैला पानी पीना पड़ता है, प्रदूषित पानी पीना पड़ता है। ऐसे में किस प्रकार से वह अपना जीवन निर्वाह करेगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछली बार जब मैं सदन में बोलकर गया, तो मुझे गैलरी में एक सज्जन, जो यहां काम करते हैं, ने मुझे मिले उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहादुरगढ़ से आता हूं, वहां इस प्रकार का प्रदूषित पानी है कि वहां पर महिलाओं को गठिया और पेट में किडनी स्टोन की बीमारियां हो रही हैं। मेरा कहने का अभिप्राय है कि हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार से यह प्रदूषित पानी शुद्ध किया जाए और जनता को शुद्ध पानी पीने का अधिकार दिया जाए। जिस प्रकार से यूरोपियन देशों में कानून में यह प्रावधान है कि टैप वाटर ड्रिंकिंग वाटर की ही क्वालिटी का होना चाहिए। इसी प्रकार के एक सख्त कानून का निर्माण करके हमें चाहिए कि शुद्ध पानी भारत की जनता को उपलब्ध कराएं जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। इसलिए मैं यही कहूंगा - रघुपति राघव राजाराम, पतितपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज उस सन्मति की हमें आवश्यकता है जिससे कि देश के लोग हृष्ट पुष्ट, वीर्यवान और आयुष्मान बनें। आज हमारी आयु धीरे-धीरे कम होती जा रही है, इसलिए देश को मजबूत बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए हमें देखना होगा कि ऐसी सुमति आए कि देश के आम आदमी को हम स्वच्छ पानी प्रदान कर सकें।

मैं कहना चाहूंगा कि आज देश में पेयजल का अत्यंत संकट है और हिमालय से, जहां से नदियों द्वारा देश को पेयजल मिल रहा है, वहां के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे देश में पेयजल का संकट हो जाएगा। एक स्टडी के अनुसार पिछले चालीस वर्षों में हिमालयी ग्लेशयरों में जबरदस्त गिरावट आई है। प्रमुख ग्लेशियरों का क्षेत्रफल 16 फीसदी कम हो गया है, हिमालय की नदियों के ग्लेशियारों के सिकुड़ने की रफ्तार ज्यादा है। एक किलोमीटर से छोटे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, चार दशकों में 30 फीसदी ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। हिमालय के ग्लेशियर ही पानी के सबसे बड़े भण्डार हैं। अतः इनके संरक्षण की दीर्घकालीन नीति बनाई जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार को शीघ्र विशेष कदम उठाने चाहिए एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जनता के मूल अधिकारों से जोड़ा जाना चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य में पेयजल के अभाव से ग्रस्त गांवों में पेयजल टैंकरों दवारा उपलब्ध कराया जाना

अति कठिन कार्य है क्योंकि यहां के कई गांव अभी भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण अति आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत लम्बित एवं अधूरी सड़क योजनाओं तथा पेयजल योजनाओं का विवरण मैं देना चाहता हूं - चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, बीरोंखाल ग्राम समूह पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना, भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, महादेव से बरसुण्ड देवता तक पूर्वी नयार नदी पम्पिंग पेयजल योजना, देवकुण्डई, तल्ली पेयजल योजना।

बवासा, घोड़ियाना, सिंदुड़ी पेयजल योजना हमारे उत्तराखंड की ऐसी कई पेयजल योजनाएं हैं। इन योजनाओं की लिस्ट बहुत बड़ी है इसलिए मैं सदन के पटल पर रख दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होगा, तो बहुत बड़ी समस्या होगी।

अंत में मैं आपको धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा,

"Where the mind is without fear and the head is held high;

Where knowledge is free;

Where the world had not been broken up into fragments by narrow domestic walls;

Where words come out from depth of truth;

Where tireless striving stretches its arms towards perfections;

Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;

Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action;

Into that heaven of freedom, my father, let my country awake."

यह हमारे टैगोर साहब ने कहा था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की आयु आयुष भारत खंड के रूप में परिवर्तित हो, हम जागें, आयुषमान बनें और दीर्घजीवी बनें, यही मैं मंगलकामना करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

I also lay a part of my speech on the Table.

ओ बडेरो ढैय्या (नागणी) पेयजल योजना

केदारगली पेयजल योजना को बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना से जोड़ना

बड़ेथ पेयजल योजना का क्रियान्वयन एवं गुराड मल्ला के लिए नई पेयजल योजना का निर्माण ।

नानाघाट पेयजल योजना ।

कोट ब्लाक के सब्दरखाल क्षेत्र (55 ग्रामों) के लिए वेलणेश्वर पम्पिंग पेयजल योजना ।

<u>जिला चमोली में लंबित पेयजल योजनाएं</u>

1. गोपेश्वर नगर से अमृत गंगा पेयजल योजना

2. विकास खण्ड गैरसैण में बड़ागांव पेयजल योजना

जिला रूद्रप्रयाग में लंबित पेयजल योजनाएं

1. तल्लानागपुर पेयजल योजना
2. तिलवाड़ा सुमाड़ी पेयजल योजना
3. रौठिया-जवाड़ी (पश्चिमी भरदार) पेयजल योजना
4. तैला पेयजल योजना
5. पिल्लू-जंगही पेयजल योजना
6. अगस्त्यमुनि पेयजल योजना
7. बसुकेदार-डांगी -सोगना पेयजल योजना

... This part of the Speech was laid on the Table.

–

–

जिला टिहरी में लंबित पेयजल योजनाएं;

1. लक्षमोली-हडीम की धार पम्पिंग पेयजल योजना, पट्टी हिसरियाखाल के लिए।
2. मलेथा-कपरोली-अकरी-बारजुला पम्पिंग पेयजल योजना पट्टी कड़ाकोट पश्चिम भाग एवं पट्टी अकरी बारजुला हेतु
3. कोटेश्वर-सिल्काखाल पेयजल पम्पिंग योजना द्वितीय चरण पट्टी चौरस एवं काड़ाकोट पूर्वी भाग
4. मुनेठ-सजवान कांडा पेयजल पम्पिंग योजना पट्टी भरपूर हेतु
5. देवप्रयाग नगर हेतु पेयजल पम्पिंग योजना
6. कोटेश्वर झण्डीधार तथा कोटेश्वर-पालकोट पेयजल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजनाएं
7. क्वीली-पालकोट पेयजल पम्पिंग योजना
8. सूरजकुण्ड-रानीताल पेयजल पम्पिंग योजना

जिला नैनीताल में लंबित पेयजल योजनाएं

1. ढिकुली में ओवर हैड टैंक का निर्माण एवं वितरण प्रणाली का पुनर्गठन ।
2. भवानी खुल्चे, भवानीपुर तडियाल, मड़ियाल में 1 कि. लाइन कार्य
3. बांगाझाला पेयजल योजना का स्वच्छ जलाशय निर्माण कार्य रामनगर शहर में ।

माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणाएं;

महोदय, इसके अलावा में आपके संज्ञान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि दिनांक 19 अक्तूबर 2006 में अपने हरिद्वार आगमन पर मा. प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी के द्वारा उत्तराखंड प्रदेश के लिए पांच पंपिंग योजनाओं के निर्माण

की घोषणा की गई थी किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक धन अवमुक्त न किये जाने के कारण इन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है । इनका शीघ्र निर्माण होना अति आवश्यक है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल

1. डांडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना

2. मुण्डनेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना

जनपद टिहरी

2. घंटाकरण ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना

जनपद अल्मोड़ा

4. दोडम ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना

5. सरयू वेलम ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना ।

पेयजल एक राष्ट्रीय समस्या है, अतएव इसके समाधान हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए ।

मोटर मार्ग

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश गांव सड़कविहीन हैं जिसके कारण वहां के निवासियों को अपनी रोजमर्रा की वस्तुएं लेने लिए कोसों पैदल चलना पड़ता है । यदि वहां कोई बीमार हो जाता है तो शहर पहुंचते-पहुंचते कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है । पेयजल ग्रस्त क्षेत्रों में सड़क न होने से पानी के टैंकर नहीं जा सकते हैं , जिससे इन क्षेत्र के लोगों को पेयजल उपलबध नहीं हो पाता । अतः पहाड़ों में सड़कों का शीघ्र निर्माण होना अति आवश्यक है ।

अपने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैंने यह अनुभव किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण में राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग विशेष रूचि नहीं ले पा रहा है जिसके फलस्वरूप या तो स्वीकृत मोटर मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं हो पाया है या निर्माण कार्य धीमी गति से किया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता परेशान है। यही नहीं बल्कि जिन मोटरमार्गों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किया भी गया है उन अधिकांश मोटरमार्गों पर बस सेवायें संचालित नहीं हो पा रही है और ये मार्ग त्रुटिपूर्ण स्थिति में अधर में लटके हुए हैं ।

उदाहरण के लिए जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देवप्रयाग-व्यासघाट मोटर मार्ग का निर्माण इसी योजना के अन्तर्गत 30 जून, 2006 को पूर्ण कर दिया गया था किन्तु अभी तक यह मार्ग बस सेवाओं के संचालन हेतु उपलब्ध ही करवाया जा सका हे । ठीक वही स्थिति अन्य मार्गों की भी बनी हुई है ।

मेरा सुझाव हे कि बिहार राज्य की भॉति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण का दायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा किसी स्वतंत्र निर्माण ऐजेन्सी को दिया जाए ताकि स्वीकृत सड़कों का निमाण यथा समय पूर्ण हो सके और इन स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु पुनरिक्षित प्राक्कलन कमेटी (Revised Estimate Commmittee) गठित करने की आवश्यकता न पड़े ।

गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में लंबित/अधूरी योजनाओं का विवरण

प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत लंबित अथवा अधूरी योजनाएं

जिला पौड़ी गढ़वाल

1. पैठाणी-बडेथ मोटर मार्ग
2. वेदीखाल-चोरखिण्डा मोटर मार्ग
3. नौडखाल-मालकोट मोटर मार्ग
4. ऐसा-चरेख मोटर मार्ग
5. मोल्काखाल-टीला मोटर मार्ग
6. कण्डलसेरा-कुराली तल्ली मोटर मार्ग
7. किल्योखाल-टकोलर मोटर मार्ग
8. बूँगी-रिक्साल मोटर मार्ग
9. पिनानी से पिनानीधार मोटर मार्ग
10. मेलसैण-चोपड़ा (स्टेज-2) मोटर मार्ग
11. सौन्दरबैण्ड-ऍडी मोटर मार्ग
12. परसुण्डाखाल-काण्डई मल्ली मोटर मार्ग
13. पीपलपानी-नौली-धारकोट मोटरमार्ग
14. रीठाखाल-पंचवटी नाई मोटर मार्ग
15. भरोली-मैठाणा मोटर मार्ग
16. चाकीसैण-जाख मोटर मार्ग
17. थापला-सासौ मोटर मार्ग
18. त्रिपालीसैंण-डुग्री मोटर मार्ग

जिला चमोली में लंबित मोटर मार्ग

1. निजमुल्ला पाणा-ईराणी मोटर मार्ग विकास खण्ड दशोली
2. घिघराणा-स्यूणबेमरू-डुमक कलकोट-ऊर्गम मोटर मार्ग विकास खण्ड दशोली
3. पुरसाडी-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग विकास खण्ड दशोली
4. विष्णुगाड चाई थैंई मोटर विकास खण्ड जोशीमठ
5 लंगासू बणसोली मैखुरा मोटर मार्ग विकासखण्ड कर्ण प्रयाग ।
6. आदिबद्री सिलपाटा भरराड़ी सैंण मोटर मार्ग विकास खण्ड गैरसैंण ।
7. ग्वाड़ रिखोली नैल मोटर मार्ग विकास खण्ड गैरसैण ।
8. नलगांव भटयाणा मोटर मार्ग विकास खण्ड नारायणबगड़ ।
9. परखाल जुनेर डुंगरी मोटर मार्ग विकास खण्ड नाराणबगड़ ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिला टिहरी विकासखण्ड कीर्तिनगर में लंबित मोटर मार्ग

1. खजरा-गोदी मोटर मार्ग
2. वागसैण-कफना मोटर मार्ग
3. कमान्द-कपरोली मोटर मार्ग

विकास खण्ड देवप्रयाग

1. रानीठौंक से राजवानकोडा बमाना मोटर मार्ग
2. मुल्यागांव-पेलेठी कोठी मोटर मार्ग

राज्य सैक्टर के अंतर्गत देव प्रयाग क्षेत्र में लंबित मोटर मार्ग

1. पौड़ीखाल भारौ मोटर मार्ग
2. पाड़ीखाल-सादनाकोट मोटर मार्ग
3. पाडीखाल-ग्वालनानगर मोटर मार्ग
4. स्यूटा-सिगोली मोटर मार्ग
5. पौड़ीखाल-कुलंर ककराडा मोटर मार्ग
6. माल्डा श्रीकोट पैडुलापाटा मोटर मार्ग
7. हिण्डोलाखाल-पलेटठी-बनगढ़ मोटर मार्ग
8. नागचौड-चागी धौंडियाधार मोटर मार्ग
9. ठुंगी-खिलेथीपंवार पलेठी बनगढ़ मोटर मार्ग
10. हिण्डोलाखाल-काण्डी-दुरोगी सिरवा मोटर मार्ग
11. हिण्डोलाखाल-भंसाकोट-ललूडीखाल सिरवा मोटर मार्ग
12. हिण्डोलाखाल-कोठी पलेड़ी मोटर मार्ग
13. ललथ सिवाली-गुजेठा मोटर मार्ग
14. बगड़वालधार-कुंड भरपूर मार्ग
15. गोल्ठा चक-व्यालनी-टकोली मोटर मार्ग
16. बरसोली बैण्ड-गौली-गुरछोली-डांगचौरा मोटर मार्ग
17. लक्षमोली तल्याकोट मोटर मार्ग
18. बागवान-जावर-हिसरियाखाल मोटर मार्ग
19. नौसाबागी-कुनडी मोटर मार्ग
20. काण्डीखाल-चन्द्रवदनी मोटर मार्ग

राज्य सैक्टर के अंतर्गत विकासखण्ड कीर्तिनगर में लंबित मोटर मार्ग

1. पैडुलाबैण्ड-रोमला सिरोला जखंड मोटर मार्ग
2. डागचौरा-गुंडोली मोटर मार्ग
3. पावबैण्ड न्यूलीनोटीपाब सेलसैण-माठुडागांव मोटर मार्ग
4. खजरा-बैजवाड़ी मोटर मार्ग
5. रौडू-जाखीगवाना ग्वाडा बेला मोटर मार्ग
6. घंडियालधार पांडवचोनीखाल मोटर मार्ग
7. चोनीखाल-नाडा धौलियाना खोंगचा पांडव मोटर मार्ग
8. चोनीखाल-कांडीऐराडी मुलाना मोटर मार्ग
9. सिल्काखाल-सरसेटसारकेना मोटर मार्ग
10. मंजाकोट-बंदारा मोटर मार्ग
11. धण्डियालधार बंदारा मोटर मार्ग
12. धण्डियालधार होदू मोटर मार्ग
13. धनजी-धारकोट सुपारडांडा मोटर मार्ग
14. कमेडा बैण्ड मालगड्डी मोटर मार्ग

<u>प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत नरेन्द्रनगर विकास खण्ड में लंबित मोटर मार्ग</u>

1. शिवपुरी तिमली मोटर मार्ग
2. रानी चौरी-भौण मोटर मार्ग
3. गूलर-चमेली मोटर मार्ग
4. गूलर-नाई मिन्डाय मोटर मार्ग
5. नाई-सिलकणी-गठियाली मोटर मार्ग
6. कौल-कौड़ारना मोटर मार्ग

<u>प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में लंबित मोटर मार्ग</u>

–

1.रामनगर-हल्द्वानी मार्ग मे बेलगढ़ से क्यारी भारी वाहन मार्ग ।

<u>राज्य सैक्टर के अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में लंबित मोटर मार्ग</u>

–

1. चन्द्रनगर जूनियर हाई स्कूल से पीपल पड़ाव मोटर मार्ग

2. धारी से राजपुर लिंक मार्ग

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

> "Having regard to the fact that there is a serious crisis of availability of drinking water in various parts of the country, particularly in Pauri Garhwal, Chamoli, Rudraprayag, Tehri Garhwal and Nainital Districts in the State of Uttarakhand and that the centrall sponsored drinking water schemes like *Swajaldhara* and Accelerated Urban WaterSupply Programme (AUWSP) are not being implemented and monitored properly, this House urges upon the Government to formulate and implement a time bound comprehensive action plan at national level to overcome the problem of drinking water."

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सतपाल जी ने एक अच्छे विषय को सदन में बहस के लिए रखा है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। सतपाल महाराज जी धार्मिक व्यक्ति हैं और वह प्रवचन भी किया करते हैं। वह शास्त्रों-पुराणों का अध्ययन भी करते हैं। इन्हें कथा करते हुए हम लोग टीवी पर भी देखते हैं। इनकी अच्छी शिष्य मंडली है, जिन्हें प्रवचन करते हैं और धर्म मार्ग बताते हैं। इसलिए धर्म के दृष्टिकोण से भी और अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी पानी के महत्व पर इन्होंने सदन का और देश का ध्यान आकृष्ट किया है।

रहिमन पानी चाहिए, बिन पानी सब सून।

पानी गए न उबरे, मोती, मानस, चून।

कवि रहीम ने कहा था कि पानी सबके लिए आवश्यक है, अगर पानी नहीं होगा तो बिन पानी के मर्द क्या और बिन पानी के चूना क्या, और बिन पानी के मोती क्या। मोती की सुंदरता तब है, सुंदरियों के गले में भी मोती की सुंदरता तब निखरती है, जब मोती पर पानी की चमक हो। मर्द में भी मर्दानगी तब है, जब उसमें पानी हो। चूना भी काम के लायक तब है, जब उसमें पानी हो, नहीं तो सूखे चूने का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए कवि रहीम ने भी पानी के बारे में इतनी सुंदर बातें कही हैं। दूसरी तरफ तुलसीदास जी ने 'रामचरितमानस' में लोक भाषा में लिखा, तो उन्होंने भी जो पंच तत्व की बात कही है,

क्षिति जल पावक गगन समीरा ।

पंचरचित यह अधम शरीरा।

उसमें भी उन्होंने जल को कहा है कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, इन पंचतत्वों की महिमा ऋग्वेद से लेकर सभी भारतीय वांग्मेय में ऋषियों ने इसे गाया है। माननीय सतपाल जी जल तत्व पर चर्चा कर रहे हैं कि पानी आवश्यक है। केवल पीने के पानी का ही अभाव नहीं है, केवल आदमी के लिए पानी नहीं, सतपाल जी, बिसलरी की बोतल से तो आदमी की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन मैं तो गोपाल हूं, अहीर हूं, हमारी भैंस और गाय कितनी बिसलरी की बोतल पीएंगी। बिसलरी की बोतल से तो हमारी बकरी की प्यास भी नहीं बुझ सकती है, तो बिसलरी की बोतल से भैंस, गाय और बैल की प्यास कहां से बुझा दोगे। जो बड़े लोग हैं, समृद्ध हैं, सम्पन्न हैं, खुशहाल हैं, वे बिसलरी का पानी पीने वाले हैं, जिनकी जेब में पैसे भी बिसलरी वाले आते हैं। कोई गाढ़ी पसीने की कमाई वाले किसान, मजदूर और दलित अपने पसीने की कमाई से बिसलरी का पानी नहीं पी सकते हैं। आज भी इस दिल्ली शहर में जहां आप जाएं, एक बार होटल में जाते हैं, पंचतारा होटल है, राजा-रानी जाते हैं, एक रात के लिए रहते हैं, हजारों रुपया किराया देते हैं, एक बार शौचालय जाते हैं, पेशाब करते हैं, फ्लश खींचते हैं, 15 लीटर पानी जाता है। दूसरी तरफ इस 15 लीटर पानी के लिए 85,000 गांवों के गरीब पांच किलोमीटर दूर पानी के लिए दौड़ते हैं।

मां गगरी लेकर जाती है, पानी लेकर आती है, जब तक वापिस आती है, तब तक पानी के बिना लाखों बच्चों के प्राण छूट जाते हैं। एक तरफ वह हिंदुस्तान है, जहां पाव भर पानी के लिए लाखों बच्चे मां की गोद में मरते हों और एक तरफ यह इंडिया है, जहां पाव भर पेशाब को धोने के लिए 15 लीटर पानी बहाया जाता है। इन दोनों हिंदुस्तान की तुलना है क्या? पानी की बर्बादी को रोको?

एक शहरी संस्कृति में एक आदमी रोज 200 लीटर पानी खर्च करता है, दूसरी तरफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के इलाके में चले जाओ, जहां एक आदमी को 10 लीटर पानी भी नहीं मिल पाता है। एक मां, एक गगरी पानी पांच किलोमीटर से लाती है और उसी पानी को पीकर वह बच्चों को भी पिलाती है और अपना काम चलाती है। हमें सबसे पहले पानी के दुरूपयोग को रोकना चाहिए। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

भगवान कृष्ण ने गीता में कहा " अन्नादभवन्ति भुतानि, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञादभवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धभव" अर्थात बादल से ही अन्न की उत्पत्ति है, और अन्न से ही प्राणि मात्र का जीवन है, अन्न बादल से आते हैं मेघ यज्ञ से बनता है, इसलिए सभी को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का मतलब केवल हवन यज्ञ नहीं है, यज्ञ माने लोक यज्ञ करना चाहिए।

सतपाल महाराज जी, आपने उस दिन व्याख्यान देते हुए कहा था कि भगीरथ ने तपस्या करके ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी को लाने का काम किया था। लेकिन आप जानते हो कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा अवतरित हुई तो शंकर जी की जटा में ही उलझकर रह गयी थीं। फिर भगीरथी को तपस्या करनी पड़ी थी, फिर भगीरथ ने शंकर जी को प्रसन्न किया था, तब जटा की एक लट को उन्होंने निचोड़ा था जिससे वर्तमान गंगा निकली थी। योजनाएं बनती हैं, प्रधान मंत्री आते हैं सरकारें आती हैं, प्रशासन के तंत्र आते हैं, विकास की गंगा आती है लेकिन अफसरशाही की जटाओं में उलझकर रह जाती है। भारत में किसी ऐसे भगीरथ की आवश्यकता है जो इन नौकरशाहों की जटाओं में फंसी गंगा को निकालकर गांव के गरीब तक पहुंचा दे, निर्धन और निर्बल की प्यास बुझा दे। योजना बनाने वालों में किसी भगीरथ की आवश्यकता है, संकल्प करने वाले की आवश्यकता है।

मैं किसान हूं, कृष्ण की संतान हूं। उन्होंने कहा था कि प्रकृति मेरी माता है, गंगा मेरी माता हैं, गो मेरी माता है, लेकिन अगर हम यहां कहें कि गो मेरी माता है, नदियां मेरी माता हैं तो न जाने साप्रदायिकता के नाम पर मेरी बातों को प्रोसिडिंग से निकलवाने के लिए कोई खड़ा न हो जाए। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में वे प्रकृति को केवल पदार्थों का समूह मानते हैं, जिसमें जंगल है, नदी है, स्थूल है, यह भौतिक है, यह पदार्थ है, लेकिन भारत की संस्कृति में प्रकृति को केवल पदार्थ नहीं मानते हैं बल्कि प्रकृति को अपनी माता मानते हैं। प्रकृति मेरी माता है, ईश्वर मेरे पिता हैं, प्रकृति के गर्भ से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मां का गर्भ जितना शुद्ध होगा, संतान उतनी बलिष्ठ होगी। अगर मां रुग्ण होगी तो संतान विकलांग पैदा होगी। इसलिए मां के गर्भ को, मां के पेट को ठीक कर दो, मां के स्वास्थ को ठीक कर दो, मां के स्तन में जितना दूध होगा, बच्चे की छाती उतनी ही चौड़ी होगी। प्रकृति में जितनी शुद्धता, पवित्रता होगी, प्रकृति जितनी स्वस्थ होगी, सबल, सुंदर होगी, उतना ही प्रकृति के गर्भ में पलने वाले प्राणी मात्र भी सबल, सुंदर और स्वस्थ होंगे। इस प्रकृति को विकृत किसने किया है? आज के युग में विज्ञान का नारा देने वाले, जो बड़े-बड़े अनुसंधान में लगे हुए लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज प्रकृति में विकृति किसने पैदा की है? प्रकृति को आपने विकृत कर दिया है। अगर प्रकृति विकृत होगी, क्रोधित होगी, प्रकृति उत्तेजित होगी, प्रकृत्ति आक्रोश में आ जाएगी, जिस दिन प्रकृति उन्माद में नाच उठेगी, उस दिन वैसे नाचेगी, जैसे नाचते-नाचते काली स्वयं अपने अंगों को काट कर अपनी गर्दन भी काट देती है और छिन्न-मस्ता के रूप में प्रगट हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के मार्फत दुनिया के वैज्ञानिकों को चुनौती देना चाहता हूं कि तुम कृष्ण के रास्ते को सीखो। कृष्ण ने कहा था, सतपाल महाराज जी आप तो कथावाचक हैं, उन्होंने कहा था कि गोवर्धन की पूजा करो। श्रीमद् भगवद के प्रसंग के मैं तीन अर्थ निकालता हूं। मेरे जैसे अनपढ़, गंवार, किसान, अहीर, जाट, गूजर, जो गांव में रहने वाले हैं, उनके बीच में कृष्ण गए, तो उन्होंने गोवर्धन का मतलब उनके लिए कहा कि गोबर धन। अर्थात् तुम्हारी गाय, भैंस, बैल का गोबर ही तुम्हारे लिए धन है। जिसके दरवाजे जितना गोबर होगा, उसके खेत में उतनी खाद जाएगी। जब खेत में गोबर की खाद जाएगी, तब उसके खेत में उतनी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जितनी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उतनी अधिक पैदावार बढ़ेगी। जितनी पैदावार बढ़ेगी, उतना घर में अनाज आएगा। जितना घर में अनाज आएगा, उतनी ही घर में सम्पन्नता आएगी। जितनी सम्पन्नता आएगी, उतनी ही उसके चेहरे पर लाली आएगी। उसके घर में उतनी ही खुशहाली आएगी। इसके बाद कुछ पढ़े-लिखे लोग आए, उनके लिए कृष्ण ने कहा - गौ वर्द्धन। ऐसा यज्ञ करो, जिससे गौ वंश की वृद्धि हो, गौ वंश का विकास हो। उसके बाद कुछ लोग ज्यादा पढ़े-लिखे आए, उनके लिए कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे लिए इसका मतलब है गौ संवर्द्धन, अर्थात् ऐसा यज्ञ करो जिससे गौ वंश का विकास हो, जिससे प्रकृति का विकास हो, जिससे ब्रह्मांड का विकास हो। समग्रता में विकास की धारा को बहाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि गंगा को अपवित्र किसने किया, गंगा के किनारे बड़े-बड़े कारखाने बनाते गए। कारखानों की गंदगी गंगा में डालते गए। मैं कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर गंगा के किनारे जिन लोगों ने बड़े-बड़े उद्योग लगाए, उन उद्योगों की गंदगी को गंगा में गिराया। वे किसान विरोधी लोग थे, वे गांव के लोगों के विरोधी थे, जानवरों के विरोधी थे। गंगा केवल शुद्धता नहीं देती है। गंगा के किनारे बसने वाली हमारी बहन, हमारी बहू, हमारी बेटी स्नान करती है। वे गंगा का जल लाते हैं, उससे खाना बनाते हैं। गंगा में हम अपनी गायों को नहलाते हैं, हमारी गाय वहां पानी पीती है। गंगा इसलिए माता है, क्योंकि उससे हमारे पशु का जीवन है, हमारे खेतों में हरियाली आती है, पशुओं में ताकत आती है और हमारे चेहरे पर लाली आती है। ऐसी गंगा नदी को अपवित्र करने का अपराध जिन्होंने किया है, वही पेयजल का संकट खड़ा कर रहे हैं। यहां पास में यमुना है। यमुना आज रो रही है कि शायद कृष्ण कहीं से चले आएं, यमुना के किनारे आएंगे, तो शायद रोते-रोते एक नई यमुना बहा देंगे, क्योंकि इस यमुना की दुर्दशा वे अपनी आंखों से देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री हक्मदेव नारायण यादव : मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रार्थना करूंगा कि पानी का संग्रहन करो, पानी का संचयन करो,

प्रबंधन करो, वितरण करो, इसके लिए व्यवस्था बनाओ। गांव के अंदर जहां-जहां जलाशय हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, बरसाती नदियां हैं, उन नदियों में चैकडेम बनाओ। पानी वहां रुकेगा, उससे कई काम होंगे। जो जलाशय हैं, उनकी खुदाई कर दीजिए, जिससे वहां पानी रुकेगा और भूमि का जल स्तर ऊंचा होगा। उससे आगे का काम कीजिए कि जो मृत नदियां हैं, बेकार पड़ी हुई हैं, जिन नदियों ने अपनी धारा बदल दी है, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं। जो मृत नदियां सूख गई हैं, उनमें खुदाई कर दो। उन नदियों को चालू कर दीजिए। वहां पानी का प्रवाह बढ़ेगा, पानी रुकेगा और भूमि का जल स्तर ऊपर आएगा। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पानी के दुरुपयोग को रोकिए, पानी का संग्रहण करिए, पानी का संचयन करिए, प्रबंधन करिए और वितरण की व्यवस्था करिए। अगर समग्रता में भारत सरकार योजना बनाए, तो कृषि का विकास होगा, पशु स्वस्थ होंगे, जीव स्वस्थ होंगे, मानव स्वस्थ होगा, नदियों को सुरक्षित कीजिए। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, अगर केवल मैं कहूंगा तो कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। मैं केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया का संसद में दिया गया भाषण याद करो।

16.00 hrs.

उस भाषण में डा. लोहिया ने कहा था कि नदियों को साफ करो, धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाओ क्योंकि वे सांस्कृतिक केन्द्र और कड़ी हैं।

इसलिए अंत में प्रार्थना करते हुए विश्व के सभी वैज्ञानिकों से प्रार्थना करूंगा और बताना चाहूंगा कि जब मैं कृषि मंत्रालय में था, आईसीएआर के वैज्ञानिकों को कहा था कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर बंद करो। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है?...(व्यवधान) तुम प्रकृति का शोषण मत करो। प्रकृति का दोहन करो, आदान करो, प्रदान करो। हम गाय को खिलाते हैं, तब दूध निकालते हैं। तुम प्रकृति को दो तब प्रकृति से लो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर आज के वैज्ञानिकों ने जो शब्द कहा है, वे वैज्ञानिक क्रूर हैं, कठोर हैं और मानवता के विरोधी हैं। एक्सप्लॉयटेशन मत करो, प्रकृति से सहयोग करो। प्रकृति की माता के समान पूजा करो। हम प्रकृति को पूजेंगे, नदियों को पूजेंगे, जंगल को पूजेंगे, यहीं से हमारी सभी समस्याओं का निदान होगा। इन सब के लिए पानी चाहिए। पानी का प्रबन्ध करो, सब मिलकर पानी का प्रबन्ध करो। सरकार भी पानी का प्रबन्ध करे, हम सब मिलकर करें। भारत के गरीब किसानों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपने पुरुषार्थ से, अपने पसीने से, अपने परिश्रम से पानी को रोको, पानी को बचाओ, समुद्र में पानी को जाने से रोको। यही पानी रहेगा तब आपके बच्चों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसी से चेहरे पर लाली आएगी। सत्ता के ऊपर निर्भर मत रहो, भारत की करोड़ों संतानों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने हाथों से देश का निर्माण करो। पानी को रोकने का प्रबन्ध करो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने मुझे देश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय पर माननीय सतपाल जी महाराज द्वारा रखे इस प्राइवेट मैम्बर बिल पर बोलने का मौका दिया।

16.02 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

मैं इस बिल को सपोर्ट करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। एक तरफ से पूरा प्रवचन आया है और दूसरी तरफ से पूरा जबर्दस्त व्याख्यान आया है। लेकिन न हम प्रवचन देंगे और न हम व्याख्यान दे सकते हैं। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने डा. राम मनोहर लोहिया जी का नाम लिया। आपको बल्कि इधर होना चाहिए। अभी सम्मानित सदस्यों ने बड़े विस्तार से पेयजल के बारे में जो यहां सदन में बातें रखीं, अगर देखा जाए तो आंकड़े बताते हैं कि सन् 2050 तक शहर की आबादी 50 प्रतिशत हो जाएगी। यही नहीं, चिंता का विषय है कि 2050 तक चीन देश को पछाड़कर भारत की जनसंख्या 1.6 अरब को पार कर जाएगी और 2025 तक जो भविष्यवाणी हुई है, भारत में अन्न की कमी होगी और पड़ौसी देशों से जल के लिए युद्ध होगा। यह भविष्यवाणी है और यह सोचने योग्य है। आज बड़ी गंभीरता से हमें इस पर सोचना होगा।

आज आप देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की कई बार यहां चर्चा हुई। ओजोन की पर्त में सूराख है। गर्मी बढ़ रही है। हमारे हिमालय पहाड़ के जो ग्लेशियर हैं, बर्फ है, वे सब पिघल रहे हैं। यहीं नहीं, पूरे एशिया में सात ऐसी बड़ी नदियां हैं जो साल भर लगातार पानी की आपूर्ति करती हैं। अरबों लोगों की प्यास पूरे विश्व में वे बुझाती हैं। जो समूचा दक्षिण और पूर्वी इलाका है, उसकी प्यास बुझाने का काम ये नदियां करती हैं। लेकिन जल पूर्ति परियोजनाओं के करीब 20 अरब डॉलर कर्ज के लिए विश्व बैंक पानी के निजीकरण पर प्रमुख वित्त पोषक बन गया है। यह भी एक बहुत चिंता का विषय है। इस पर भी हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पानी की जो समस्या हमारे पूरे विश्व में है, मैं केवल भारत देश की बात नहीं करता, पूरे विश्व में जो समस्या है, उसका सबसे मुख्य कारण देश की बढ़ती हुई आबादी है।

शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। भू उपयोग में भी परिवर्तन हो रहा है। जमीन के अंदर बढ़ता दोहन चाहे खनन या पानी के रूप में हो, इसका मुख्य कारण है। खास तौर से वनों का उन्मूलन और खनन हो रहा है, पत्थरों की तुड़ाई हो रही है। हिमालय में जल संसाधनों

का समूचा तंत्र बदली जलवायु के कारण बदल रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। यही कारण है कि आज पूरे विश्व में पेयजल की समस्या हो रही है। जहां तक पानी के दुरुयोग की बात है। अगर हम देश के बड़े नगरों की तरफ ध्यान दे तो पता चलेगा कि मुम्बई में वाहन धोने के लिए 50 लाख लीटर प्रति दिन पानी खर्च होता है। हम अक्सर ट्रेन से जाते हैं तो देखते हैं कि पानी बहता रहता है और मुम्बई, दिल्ली, चैन्नई में बड़ी पाइपलाइनों के वाल्व खराब होने से 17-44 प्रतिशत पानी बहकर नालियों में चला जाता है। यह चिंता का विषय है। हमने सदन में सूखे के विषय पर विस्तार से चर्चा की है। अगर हम दूसरे देशों की तरफ देखें, जैसे इजराइल को ही ले लीजिए। वहां केवल 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है लेकिन यह देश अनाज की पैदावार भी करता है और दूसरे देशों को भी निर्यात करता है। यह वहां की स्थिति है। आज हम भारतवर्ष की स्थिति देखें तो यहां जलवायु परिवर्तन के कारण हमेशा चार साल में सूखे की स्थिति आती है। यहां 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के बावजूद भी अनाज की कमी बराबर बनी रहती है। इसी सदन में चावल निर्यात के घोटाले को लेकर चर्चा की गई थी। हमारी खेती पर पानी के कारण बहुत प्रभाव पड़ता है।

महोदय, पिछले 50 वर्षों में पानी को लेकर 37 भीषण हत्याकांड हुए हैं, यह रिकॉर्ड बताता है। आज भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पेयजल की बहुत समस्या है, जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे देश की भारतीय महिलाएं करीब चार किलोमीटर दूर से घड़ों में पानी भरकर लाती हैं तब जाकर उनको खाना बनाने और पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पाता है। यहां कई माननीय सदस्य तेलंगाना तथा अन्य क्षेत्रों के बारे में बता रहे थे। जहां तक पानी के संक्रमण की बात है। मैं पानी के विषय में बताना चाहूंगा कि पानी कितना प्रदूषित हो गया है। आज 22 लाख व्यक्तियों की मृत्यु प्रति वर्ष जल प्रदूषण के कारण हो रही है। पृथ्वी के 70 प्रतिशत भाग में एक अरब 40 घन किलोमीटर पानी है। समुद्र में 97.5 प्रतिशत खारा पानी है। ध्रुव प्रदेशों में बर्फ के रूप में एक परसेंट पानी है। नदियों, सरोवर, कुओं झरनों और झीलों में एक प्रतिशत पानी है जो पीने लायक है। इस तरह से एक प्रतिशत में 60 प्रतिशत पानी की खपत खेती उद्योग और कलकारखानों में होती है। इसके अतिरिक्त 40 प्रतिशत पानी का हिस्सा भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने, सफाई और अन्य कार्यों में खर्च करते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें तो हम सुबह नित्य क्रिया से विरक्त होते हैं और उसमें ब्रश भी करते हैं। बहुत लोगों की आदत है कि ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं। इस तरह से केवल ब्रश करने में 25-30 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। बाथ टब में नहाने के लिए प्रति व्यक्ति 300-500 लीटर पानी चाहिए और यह खर्च हो रहा है। दुनिया के दो अरब लोग स्वच्छ, सुरक्षित पेयजल से आज भी वंचित हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है। हमें इस विषय पर सोचना पड़ेगा। विश्व में प्रति दस व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों को भी शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। पेयजल के बारे में इस सदन में चर्चा होती है, हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि जो पानी बेकार जा रहा है, फिजूल जा रहा है इसे कैसे संरक्षित करें क्योंकि ऐसा करने से ही इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। हम प्रति वर्ष छः अरब लीटर बोतल बंद रेल नीर या बिस्लरी पानी पीते हैं। हम प्रतिवर्ष छः अरब लीटर बोतलबंद पानी पीते हैं। आज बोतल का पानी भी महंगा है। रेल नीर और बिसलरी बॉटल दस-बारह रुपये में मिलती है। अन्यथा पेयजल की ऐसी-ऐसी बोतलें आई हैं, जो साठ रुपये लीटर है। दूध से भी ज्यादा उसके दाम हैं। आज हमारे यहां पानी महंगा है और दूध सस्ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि लोग पानी न पीकर दूध ही पीयें तो हमारा पेयजल का संकट दूर हो सकता है।

दूसरी तरफ अगर फलों को हम संरक्षित करें तो उसमें भी बहुत द्रव्य होता है। आलू, अनानास में 80 प्रतिशत और टमाटर में 95 परसैन्ट पानी होता है। मानव को पीने के लिए प्रतिदिन तीन लीटर पानी चाहिए। पशुओं को पचास लीटर पानी चाहिए। गाय का एक लीटर दूध पाने के लिए हमें आठ सौ लीटर पानी खर्च करना पड़ता है। एक किलो गेहूं एक हजार लीटर पानी खर्च करने के बाद हम प्राप्त करते हैं। एक किलो अनाज उगाने के लिए हमें चार हजार लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। भारतवर्ष में 83 प्रतिशत पानी खेती और सिंचाई में उपयोग होता है। इस तरह से हमें वर्षा का पानी भी बचाना पड़ेगा। जैसा हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा कि हमारे देश में तमाम नदियां हैं। पहले नदियां हजारों की संख्या में थी, लेकिन अब सूखते-सूखते बहुत सी नदियों का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अब मेरे ख्याल से केवल सैकड़ों की संख्या में छोटी-मोटी नदियां बची हैं। आज भी यदि हम गांवों, मौहल्लों में स्थित तालाबों को देखें तो उनकी संख्या में कमी आई है, समय के साथ ये गायब हुए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि तालाबों पर जो इनक्रोचमैन्ट है, वहां तमाम लोगों ने तालाबों को पाटकर अपने मकान बना लिये हैं, उन्हें डिमॉलिश किया जाए। नरेगा में भी तमाम स्कीमें है। हमेशा सरकार भी कहती है और यहां अपने उद्बोधन में सब लोगों ने भी हमेशा इस बात को कहा है कि गांव-गांव में तालाब होना चाहिए और वर्षा के पानी को हम संरक्षित करें। तभी हमारा भूगर्भ स्टेटा मेनटेन रहेगा। इस तरह से पानी को संचय करके हम उसे अपने उपयोग में ला सकते हैं।

जहां तक प्रदूषित पानी का सवाल है, इसकी व्यवस्था के बारे में मैंने आपसे अभी विस्तार से कहा है कि आज पानी एक तरह से बीमारियों का स्रोत बन चुका है। दूषित पेयजल से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, चाहे डायरिया, आंत्रशोथ, चर्म रोग, पोलिया हैपिटाइटिस और कैन्सर हो, इस तरह की तमाम बीमारियां आज पानी के कारण होती हैं। चूंकि हम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में काफी पीछे हैं। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा।

हम भूजल से 80 प्रतिशत पानी का दोहन करते हैं और दो प्रतिशत पानी हम नदियों, झीलों और तालाबों से प्राप्त कर पाते हैं। खेतों में हम जो उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां प्रयोग करते हैं, उनके कारण भी जमीन से दोहन किये गये पानी में मैटल और प्रदूषण होता है और वह पानी खारा भी होता है, जिसके कारण तमाम बीमारियों का जन्म होता है।

यदि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो विश्व में प्रतिवर्ष चालीस लाख बच्चे जलजनित बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। चाहे वह डायरिया, आंत्रशोथ, टायफाइड, डिसेन्ट्री और पोलियो हो। आज इस तरह के तमाम रोग हमारे बीच में फैले हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमने पानी के विषय में नहीं सोचा और पानी को संरक्षित नहीं किया तो आने वाले समय में विश्व युद्ध केवल पानी के लिए होगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं सतपाल महाराज जी द्वारा प्रस्तुत प्राइवेट मैम्बर बिल का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मुझे इस बात की इंतिहा खुशी है कि हमारे साथी ने इस किस्म का सवाल इस बिल के जरिये पैदा किया है और जो प्राइवेट मैम्बर बिल सदन में लाया गया है, मैं भी चाहता हूं कि इस पर संजीदगी से सबने पहल करनी चाहिए। पानी एक जिंदगी है। चाहे वह जमीन हो या आसमान हो, सूखा आसमान भी बुरा लगता है जब बरसात के दिन आते हैं। जमीन भी देखें तो खाने को पड़ती है।

यहां तो ड्रिंकिंग वाटर का सवाल है। जब तक पानी रिचार्ज नहीं होगा तो वह खत्म हो जायेगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं हो सकता है। सब से इम्पार्टेंट बात यह है कि आज हमारी नदियां, नाले सूख रहे हैं। हमने छोटी उम्र में अपने इलाके में देखा कि हमारे देखते-देखते बहुत सी नदियां 10-20-30 साल में सूख गईं। आज उन सूखी जगहों को देखने से मन में आता है कि कभी इनमें पानी चले। लेकिन हमें इसका कारण ढूंढना होगा कि जब इनमें पानी नहीं होगा तो हम लोगों को पीने के लिये पानी कहां से मिलेगा?

सभापति जी, सब से ज्यादा इम्पार्टेंट हमारे जंगल हैं। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो बहुत ही सुन्दर है। वह सुन्दरता पहाड़ों से हैं, पेड़ों से हैं, जड़ी-बूटियों से हैं लेकिन आज वे धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। आज बड़े-बूढ़े दरख्त दिखाई देते हैं और अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि छोटे जंगल दिखाई नहीं देते हैं। मैं थोड़े दिन पहले अपने क्षेत्र में गया था। बहुत से लोगों ने पटनी टॉप का नाम सुना होगा। वहां से सनासार 17 किलोमीटर है जहां तक मैं पैदल गया। टोटल पहाड़ नंगा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग पहाड़ों पर बड़े बड़े मैदान पायेंगे। जब पहाड़ों पर मैदान नहीं थे, वहां पहाड़ों पर पेड़ थे, सुन्दर जड़ी-बूटियां थीं। आप सब को मालूम होगा कि हर साल जंगलों में आग लगती है। लेकिन यहां जानबूझकर एक-दो-तीन-चार बार आग लगाई जाती है। लोगों में जागरूकता नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से ठीक प्लानिंग नहीं है। पीने का पानी पहाड़ों से चलकर आता है लेकिन लोग जमीन से पानी निकालना चाहते हैं। जैसे शरीर से उसका खून निकाल लिया जाये तो वह जिन्दगी कितने दिन रहेगी, ऐसी हालत जमीन की हो गई है। जमीन में ड्रिप ड्रिलिंग से पानी निकाल रहे हैं, हैंड पम्प से पानी नहीं निकलता है, दो पाइप और डाल दो, तो पम्पिंग सैट से पानी कैसे निकलेगा? हर साल पानी 20 फीट नीचे जा रहा है। आप देखिये कि अगर उधर पानी है तो इधर कैसे लगाना चाहिये, कैसे रिचार्ज करना है, वापस कैसे लाना है? लोग तो कह रहे हैं कि हम अपने यहां बारिश करवा लेंगे। रास्ते में बादल अपने ऊपर गिरा लेंगे। नेचर को इतना इम्बैलेंस किया जा रहा है, इतना ह्रास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग अपनी प्रकृति, भगवान ने जो खूबसूरती बनायी है, उसे हम खुद बरबाद कर देंगे। मेरा सबमिशन है कि हमारा देश सब से सुन्दर इसलिये है कि यहां छः ऋतुयें होती हैं। किसी देश में ऐसा नहीं है। कहीं पर दो हैं तो कहीं चार हैं। हमारे यहां वसंत ऋतु है। इस देश को किसने बढ़िया बनाया है? हिमालय ने, पेड़ों ने, मैदानों ने क्योंकि आपसी तालमेल है।

सभापति जी, हमारे देश के दो-तीन डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको इस बात को सख्ती से लेना चाहिये। हम लोग जब मंत्री बनते हैं तो मांगकर डिपार्टमेंट चाहते हैं। हम उस मंत्रालय में जाना चाहते हैं जहां देश का और समाज का काम कम हो, नेचर का कम हो लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम जरूर मिलना चाहिये। इन सब में इम्पार्टेंट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट है। पानी एक तरह से सोना-चांदी है। आप उस पानी को ख्वामख्वाह बरबाद कर रहे हैं। जब आप प्लांटेशन नहीं करोगे तो कागज़ों में देखोगे कि इन्होंने इतने प्लांट्स लगाये हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारे सिर पर भी चार-चार लग गये हैं, फिर भी वे पेपर्स पूरे नहीं होते हैं।

कागज भरे हुए हैं, पूरे देश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कागज भरकर रखे हुए हैं कि उसने लाखों पेड़ लगाये हैं। हमारी तारीफ में लिखा गया है, गीता, रामायण, ऋग्वेद में लिखा गया है कि हर आदमी को 16 पेड़ लगाने चाहिए। 16 पेड़ लगाने का कुछ मतलब है, पांच तालाब लगाने का कुछ मकसद है। मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी पहाड़ में जाए, कंडी में जाए, मैदानों में जाए, हमारे इलाकों में जाकर देखे, हर बंदे के पास एक दरांत होता है, दरांती होती है, कुल्हाड़ी होती है और हर बंदा डेली कुछ न कुछ काटने के चक्कर में होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पेड़ लगाने के चक्कर में कोई नहीं होता है। मेरी कहना है कि हमारे बुजुर्गो ने तालाब बनाये, कंडियों में तालाब बनाये, पहाड़ों में तालाब बनाये, मैदानों में तालाब बनाये और तालाब के किनारे उन्होंने जबरदस्त प्लांटेशन की थीं। जैसे-जैसे सूर्य घूमता था, उसकी छाया उसके ऊपर रहती थी। आज क्या हो रहा है? पहले हमने उसके किनारे के प्लांट काटे, फिर तालाब सूखा, पीछे से पानी आता था, उसे रोका, हर जगह इन्क्रोचमेंट हो गया है।

मेरी जनाब से विनती है, हमारे रूरल मंत्रालय को देखने वाले, गांवों को देखने वाले बहुत ही सुन्दर मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मेरी इनसे और वाटर कंजर्वेशन करने वाले दोनों मंत्रियों से सबमिशन है कि एक कांप्रिहैंसिव प्लान बनाइए जिससे देश का कोई तालाब बिना पानी के नहीं रहे। आप प्लान कीजिए कि जो तालाब बर्बाद और तबाह हुए हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए, इस पर गौर किया जाए। जो प्लांटेशन कट गयी है, तबाह हो गयी है, उसे जल्दी लगाया जाए। मैं कहता हूं कि इसका ठेका कोई नहीं उठाता है। मैं इस देश की फ्री सर्विस करने के लिए तैयार हं। सरकार मेरे कहने पर प्लांट लगाये, मेरे कहने पर अफसर बनाये, मैं कोई पैसा नहीं लंगा। इस

जंगल वाले डिपार्टमेंट को मैं सुधारूंगा, पानी वाले डिपार्टमेंट को मैं सुधारूंगा, आप ठेका मुझे दे दीजिए, मैं पैसा नहीं लूंगा, विदआउट मनी ठेका मैं लूंगा। मेरी जनाब से विनती है, मैं बहुत दुखी होता हूं, जब ऐसी हालत देखता हूं।

महोदय, आप सभी ने वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में सुना होगा। उदाहरण के लिए चाहे देहली कह लो, अठियालता कह लो, अठूंड कह लो, ढांडुगनू कह लो, कल्फेत्र कह लो, ऊपर कह लो, नीचे कह लो, जब वह बनती है तो उसका नाम वाटर सप्लाई स्कीम रख लिया जाता है। उसके बाद जब वह पानी नहीं देती है तो लिखा जाता है improvement of water supply scheme, फिर लिखा जाता है, upgradation of water supply scheme. इस तरीके से वही वाटर सप्लाई स्कीम चलती रहती हैं और वह लोगों को पीने का पानी नहीं देती हैं।

महोदय, आपसे विनती है कि जब तक आप इन प्रतारकों को सीधा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सारी स्कीमें, सारी कहानियां, सारा सिलसिला, लंबी-चौड़ी कहांनियां, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जमीन पर कुछ नहीं है। मेरी विनती है कि जितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हर डिपार्टमेंट को थ्रू-स्कीम जाता है, यह जानकारी आपके पास भी आती होगी, कोई भी एमपी ऐसा नहीं है जो मेरे से कम जानता हो, सब मेरे से ज्यादा जानते हैं। सब जानते हैं, मिनिस्टर जी भी जानते हैं, लेकिन जब स्कीम बन जाती हैं, गुस्सा न करें, वहां परेशानियां कैसे-कैसे बढ़ती हैं, इसका कोई इलाज कीजिए। कोई ऐसी दवाई दीजिए, जिससे नीचे वाला स्ट्रक्चर ठीक हो जाए। किसी को कोई फिक्र नहीं है।

महोदय, पानी नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं रहेगा। पहले बीजेपी वालों ने पानी पिया, यशवंत सिन्हा जी ने पानी पिया, उधर एक ने और पानी पिया फिर हमारे विदेश मंत्री जी ने पानी पिया, बाहर जाकर मैंने भी पानी पिया और अभी सतपाल महाराज जी भी पानी पीकर आये हैं। मेरी जनाब से विनती है कि सभी को पानी की बहुत जरूरत है। खाना खाने के बारे में आपको बताऊं, मैं यहां आकर एक बजे तक भूखा बैठा रहता हूं, लेकिन पानी के दो-तीन गिलास पी लेता हूं। इसके बाद दोपहर को खाना खाता हूं। जब मुझे बोलना होता है तो मैं टिका रहता हूं, चाहे भूखा रहूं, लेकिन पानी जरूर पी लेता हूं। पानी ही मुझे बचा रहा है, इस पूरी सृष्टि को बचा रहा है, पानी ही सारी चीजों को बचा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि पानी को कौन बचा रहा है? पानी को कोई नहीं बचा रहा है। कैसा गरीब पानी है, कैसा शरीफ पानी है। पानी कैसे बचे, जो सबको बचा रहा है, उसे कोई नहीं बचा रहा है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सबमिशन है कि the Government must take serious note about that. अगर आप हम अवाम को पीने के लिए पानी नहीं दे सके, खेत-खलियान को पानी नहीं दे सके, प्लांटेशन को पानी नहीं दे सके, अवाम को पानी नहीं पिला सके, हमारे यहां पानी तो है, लेकिन पानी का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सके तो यह हमारी अक्षमता है। हमारे बुजुर्गों ने बड़े अच्छे प्लान बनाए थे। जगह-जगह बावलियां और तालाब लगाए थे। हम लोग क्या कर रहे हैं?

मेरी इस सदन के माध्यम से सबसे यही अपील है कि हर आदमी अपने हिस्से के पेड़ लगाएं, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से भी लगवाएं। इसके अलावा हमारे जितने मंत्रालय हैं, जो कि पानी को डील करते हैं, जो पानी को सेव कर सकते हैं, वे इस बात का सख्ती से नोटिस लें, चाहे अन्य कोई काम हो या न हो क्योंकि यह बिल्डिंग्स, यह इमारतें, यह मीनारें, इनकी कोई कीमत नहीं रहेगी यदि इंसान, जानवर, पक्षी और जमीन प्यासी रहेगी। मेरा निवेदन है कि इसका सीरियसली नोट लिया जाए।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। श्री सतपाल महाराज बधाई के पात्र हैं, जो पेयजल समस्या के निदान पर प्राइवेट मैम्बर्स बिल लाए और हम लोगों को सरकार को कुछ कहने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, कहावत है- जल ही जीवन है। यानी बिना जल के जीवन की कल्पना, सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज पूरे देश में घोर पेयजल संकट है और आने वाले समय में यह संकट और गहराने वाला है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है और यह बतलाया कि आखिर यह पेयजल संकट क्यों हो रहा है? प्रकृति से छेड़छाड़ हमने शुरू की और जलवायु में परिवर्तन शुरू हो गया, जिसकी वजह से मानसून नहीं आया।

महोदय, मैं बिहार राज्य से आता हूं। उसके 17-18 जिलों में आज पेयजल संकट पैदा हो गया है। गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और पटना में पेयजल संकट चरम सीमा पर पहुंच गया है। जलस्तर नीचे गिर गया है। आप और सरकार भी इस बात को जानती है कि जब तक वाटर रिचार्जिंग नहीं होगी, तब तक जो पेयजल हम भू-जल से उत्पन्न करते हैं, उसकी रिचार्जिंग कैपीसिटी धीरे-धीरे

समाप्त होती जा रही है। जिस समय विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, उस समय हमारे पूर्वजों ने हर गांव में तालाब बनवाए। बिहार में इसे हम लोग आहर कहते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के काल में पाटलिपुत्र के आस-पास में आहरों का निर्माण हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे उनका अतिक्रमण होता जा रहा है। उनके रखरखाव के लिए सरकार बहुत भाषण करती है। वर्ष 2004-05 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम सिंचाई के परम्परागत स्रोतों का जीर्णोद्धार करेंगे।

महोदय, आहर में जल संचरण होता है। उसमें पानी रिचार्ज होकर जमीन के अंदर जाता है और उसका दोहन करके उसे पीने के पानी के रूप में उपयोग लाया जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, बिहार में कुछ इलाके ऐसे हैं और उन्हें मैंने अपने चुनाव के समय में झेला है। नक्सलवाद पर चर्चा हो रही थी, नक्सलवाद कैसे रुकेगा, पीने के पानी से उसका भी संबंध है। जहानाबाद के संसदीय क्षेत्र में गया जिला है और यह देश का महत्वपूर्ण जिला है। मेरा संसदीय क्षेत्र जहानाबाद है। अतरी एक विधानसभा है, चुनाव के समय में वहां नक्सलियों ने मुझे घेरा। मैं जानता नहीं था कि यह पहाड़ों का इलाका है, चुनाव प्रचार के समय मैं वहां गया था। मैं डर गया कि पता नहीं मेरे साथ यहां क्या होगा। मुझे वहां लोग ले गए और ले जाने के बाद एक ही बात कही कि आप केवल पीने के पानी का प्रबंध कर दें। आप चल कर देखें कि वहां लोग कैसे पीने का पानी पी रहे हैं, वहां कैसा पानी है। वहां कुंआ है, लेकिन उसमें से एक बाल्टी पानी निकालने में आधे घंटे का समय लगता है। वह पहाड़ी इलाका है, जब सीपेज़ होता है, अंदर से पानी निकलता है तब एक बाल्टी पानी उसमें आता है।

सभापति महोदय, मैंने माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्य मंत्री को आकर यह बात बताई कि मैं चुनाव प्रचार में था और मेरे साथ इस प्रकार से वहां व्यवहार किया गया। एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि आपका जो पेयजल आपूर्ति का प्रोजेक्ट है, वह हाथी के दांत की तरह है। पूरे देश में कहीं एक भी पेयजल आपूर्ति योजना कारगर नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि आप पीने के पानी के लिए छोटी-छोटी योजनाएं बनाएं। हमारे जो टैंक्स और तालाब हैं, उनका जीर्णोद्धार करिए। आज जो अतिक्रमण हो रहा है, वहां पक्के मकान बन रहे हैं, उसे उससे मुक्त कराएं। आप जो एमपी फंड देते हैं, यह मामला उससे जुड़ा हुआ है। हम जब असेम्बली में मेम्बर थे तो एक करोड़ साल में बिहार में मिलता था। यहां दो करोड़ मिलते हैं, इतने रुपए में हारने के लिए 33 परसैंट दुश्मन खोजने की जरूरत हम लोगों को नहीं है, फंड ही दुश्मन है। पीने का पानी जहां रिग मशीन से आए, केवल पीने के पानी के लिए एमपीज़ को भारत सरकार स्पेशल एलोकेशन करे और स्पेशल अनुशंसा पर वह रुपया एमपी को नहीं मिले। वह पहाड़ी इलाका है, मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं दोबारा उस इलाके में जाऊंगा और पीने के पानी का इंतजाम नहीं करूंगा तो एक एमपी का हश्र क्या होगा, इसकी आप कल्पना करिए। जहां कमांडर लोग बैठे हुए हैं, मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं, यह घटना मेरे सामने घटी है। मेरे साथ किस तरह से उन लोगों ने व्यवहार किया। उन्होंने मुझ से एक ही बात कही कि जब आप एमपी बन जाएं तो पीने के पानी का इंतजाम करके आना। अगर पीने के पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो आप नक्सलवाद और दूसरी चीजों को नहीं रोक सकते। सृष्टि को नहीं बचा सकते।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि एमपीज़ को, उनके इलाके में पीने के पानी के लिए स्पेशल फंड मुहैया कराएं ताकि लोग पानी पीकर आगे अपनी तरक्की और उन्नति की भविष्य में कल्पना कर सकें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सतपाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, पेयजल के संकट को देखते हुए पूरे देश में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, पेयजल संकट सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में विश्व में पेयजल के लिए युद्ध होंगे। आज हमारे देश में भी यही हालत है - सूखा, बाढ़ और कहीं न कहीं पूरे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में, जिस राजधानी दिल्ली में हम रहते हैं, हर जगह पेयजल का संकट बना हुआ है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उत्तराखंड के अंदर, गंगा, यमुना उसी क्षेत्र से निकलती है, जहां से नदियां निकलती हैं और वहां के लोग और खेत प्यासे हैं।

सभापति महोदय, इस संदर्भ में एक नयी राष्ट्रीय नीति के दृष्टिकोण की जरूरत है। पेयजल का जो सवाल है, हम हर साल देख रहे हैं, इसके लिए राष्ट्रीय प्रबंध की जरूरत है। हम ग्राउंड वाटर का पानी निकाल रहे हैं, धीरे-धीरे जमीन के पानी का स्तर, जैसे हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हर बार सौ-सौ मीटर पाइप नीचे जा रहा है। मैं हिमालय क्षेत्र से आया हूं, गंगा और यमुना का मूल स्रोत वही है। हर साल 10-15 मीटर हमारा ग्लेशियर पीछे सरक रहा है।

सभापति महोदय, पूरे हिमालय क्षेत्र के अन्दर, जम्मू-कश्मीर से देखें, तो पूरी हिमालयन बैल्ट में दिन प्रति दिन ग्लेशियर्स खिसक रहे हैं। लोगों के पीने के पानी का सवाल हो या कृषि हेतु पानी का सवाल हो, हिमालय इस देश के पेय जल का सबसे बड़ा स्रोत है।

हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों के लिए, फिर वे चाहे हमारे देश की हों या नेपाल की हों, उनके लिए एक दीर्घगामी स्कीम जब तक नहीं बनाई जाएगी, तब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा।

महोदय, वनों का पूरे हिमालय क्षेत्र में धीरे-धीरे घटाव हो रहा है। हिमालय क्षेत्र में सिर्फ मोनोकल्चर है। वहां चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों और मिक्स पेड़ों को लगाने की जरूरत है। इसलिए हमें दो-तीन सवाल देखने होंगे। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए हमें जल प्रबन्धन करना होगा। वाटर कंजर्वेशन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक छोटी सी नदी कोसी है। वहां के वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया, तो पता चला कि हर साल बरसात का जो पानी जमीन में जाता है वह प्रति वर्ष घटता जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति का स्रोत कुमाऊं को माना जाता है। वहां के वैज्ञानिकों ने पिछले दो-तीन सालों में अध्ययन किया, तो पता चला कि हर वर्ष पानी बरसता है, वह कम से कम 33 प्रतिशत जमीन के अंदर जाना चाहिए था, जो जमीन के अंदर जाकर रीचार्ज होकर पेयजल का स्रोत बनता है। आज उसकी मात्रा केवल 13 प्रतिशत रह गई है और कहीं-कहीं तो केवलमात्र 5 परसेंट ही पानी जमीन के अंदर जाता है। उस कोसी नदी पर उस क्षेत्र के संपूर्ण इलाके में रहने वाले लोग निर्भर हैं। अलमोड़ा शहर उस पर निर्भर करता है। उसी पर बगल में बसा रानीखेत निर्भर करता है। पिथौरागढ़ में जो सरयू नदी है, वह शहर उसके पानी पर निर्भर करता है। नदियों में जो पानी आ रहा है, उसकी हर साल मात्रा कम होती जा रही है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि हम बरसात के पानी को कैसे जमीन के अंदर ले जाएं। जितना ज्यादा पानी जमीन के अंदर जाएगा, उतना ही पानी हमें रीचार्ज होकर नदियों में मिलेगा।

महोदय, मैं प्रश्नोत्तर काल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर सुन रहा था, जिसमें बताया गया कि देश में पानी की कमी को दूर करने के लिए देश की विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ा जाए। मैं बताना चाहता हूं कि जब नदियों में पानी ही नहीं होगा, तो नदियों को आपस में जोड़ने का क्या लाभ होगा। जब नदियों में पानी होगा, तभी तो उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। अब सवाल है कि नदियों में पानी कहां है? प्राकृतिक धारा को आप रोकना चाहते हैं, यह कैसे सम्भव होगा। इसलिए मूल प्रश्न यह है कि जो बरसात का पानी है, उसे सागर में जाने से कैसे रोका जाए। जो हमारा पानी का प्रबंध-तंत्र है, वह इस बात को देखे कि जो पानी देश में बरसता है, वह जमीन के अंदर कैसे भेजा जाए।

महोदय, पानी की व्यवस्था करने के लिए वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट है, पेयजल का विभाग है और सिंचाई का विभाग है। पीने के पानी और सिंचाई के लिए लाखों और करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं, लेकिन इन सब विभागों के पास पानी के कंजर्वेशन की कोई योजना नहीं है। फॉरेस्ट विभाग पानी के कंजर्वेशन के लिए काम करेगा और पानी के उपयोग के लिए पेयजल और सिंचाई विभाग काम करेंगे। जब तक इन तीनों विभागों में कोआर्डीनेशन नहीं होगा, तब तक पानी का ठीक प्रकार से प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

महोदय, बड़े-बड़े शहरों में पेयजल की समस्या है। मैं एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्थित रेणुका झील पर डैम बनाकर पानी दिल्ली पहुंचाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बांध बनेगा, तो हजारों लोगों को वहां से इधर-उधर हटाया जाएगा और वे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, तब एक शहर की प्यास बुझेगी। यह कौन सा तंत्र है, जहां हजारों-लाखों लोगों को उजाड़कर, जो प्रभावशाली शहर है, जहां प्रभावशाली लोग बसते हैं, उनकी पेयजल की समस्या को दूर किया जाए?

महोदय, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। टिहरी में बहुत बडा डैम बना। हमने जिस शहर में अपना प्रारम्भिक जीवन जिया, आज वह शहर टिहरी डैम में डूब रहा है। हमें आज भी यह विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा शहर डैम में डूब रहा है। वह शहर डैम में डूब रहा है और दिल्ली की प्यास बुझा रहा है, लेकिन वहां के लोग आज भी प्यासे हैं। टिहरी की बहुत बड़ी परियोजना को सब लोग देखते हैं, लेकिन जो लोग उस परियोजना के कारण उजड़े हैं, उन उजड़े हुए लोगों की दास्तान को देखने वाला हमारे यहां कोई नहीं है। वहां से जो लोग उजड़े उनमें से कुछ ऋषिकेश और कुछ हरिद्वार में बस गए, लेकिन आज भी उनके संकट को कोई देखने वाला नहीं है।

महोदय, इस शहर में बड़े-बड़े बिल्डर, लाखों और करोड़ों की लागत से बड़े-बड़े भवन बना रहे हैं। सरकारें अपने-अपने भवन निर्माण कर रही हैं। सब लोग कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। मेरी सब्मीशन है कि दिल्ली या अन्य शहरों में बनने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अनिवार्य नियम बना देना चाहिए। इस देश में चाहे सरकारी भवन हों, चाहे प्राइवेट भवन हों या कोई भी भवन हों, चाहे राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के भवन हों, जिनके लिए आप म्युनिसिपेलिटी के कानून बनाते हैं, उनके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नियम अनिवार्य कर दिया जाए।

आज राज्य की सरकार पेयजल के लिए लाखों-करोड़ रुपया हर साल देती है। लेकिन वहां पर यही होगा कि पेयजल के जो नल लगेंगे, उनमें हर साल करोड़ों रुपये का इन्वैस्टमेंट होगा, जिसमें नौकरशाहों का, इंजीनियर्स का, ठेकेदारों का और हम जैसे राजनेताओं का हो सकता है कि घर भर जाये, लेकिन लोगों की हालत नहीं सुधरने वाली है। हम लोग यहां भी अभी मांग कर रहे हैं कि जमीन के पानी को निकालने के लिए हैण्डसैट लगाये जायें। इसमें भी नियम बनने चाहिए कि जमीन से नीचे के पानी को, ग्राउंड वाटर को कितने नीचे तक निकालने की परमीशन दी जाये।

आज इस देश के अन्दर पीने के पानी में तीन तरह के लोग हैं। एक-मिनरल वाटर नीर से लेकर हिमालयन वाटर की बोतल पीने वाले लोग हैं। इनका परसेंटेज मेरे ख्याल से पांच या दस होगा। उसके अलावा दूसरे जो टैप वाटर से पानी पीते हैं और तीसरे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जानवर जिस पानी को पीते हैं, लोग भी उसी पानी को पीते हैं। आज सबसे बड़ा संकट यह है कि जो इस देश के करोड़ों लोग हैं, जो इस देश के आम आदमी हैं, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके पेयजल के संकट को दूर करने के लिए जब तक एक लॉंग टर्म योजना नहीं बनाई जायेगी, तब तक मैं नहीं समझता कि इस पेयजल के संकट का कोई स्थाई समाधान हो पाएगा।

उसके लिए स्थाई समाधान यही है कि बरसात का जो पानी हर साल आ रहा है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साल भर में बरसात का जो पानी आता है, उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ। पिछले 50 सालों से जो साल भर पानी गिरता है, उस पानी में कोई अन्तर नहीं आया, लेकिन ऋतु चक्र बदल गया है। आज उसी पानी के संरक्षण की जरूरत है। आज गांवों के अन्दर और फोरैस्ट में चौड़ी पत्ती के वृक्षों को लगाने की जरूरत है, छोटे-छोटे ट्रेंच बनाने की जरूरत है, पानी के कंजर्वेशन की जरूरत है। हमारे देश में परम्परागत ज्ञान भी था, हमारे पास ट्रेडीशनल ज्ञान था, नोलिज थी, कहीं छोटे-छोटे गांवों के अन्दर पानी के तालाब थे, आज नरेगा की स्कीम के माध्यम से उन सब के रिवाइवल की जरूरत है, उन सब के संरक्षण की जरूरत है। हमारे पास जो परम्परागत ज्ञान था, उस ज्ञान को और जो आधुनिक विज्ञान है, दोनों के बीच में समन्वय की जरूरत है। बरसात के पानी के लिए, रेन वाटर के लिए चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, प्राइवेट क्षेत्र में, चाहे शहरी क्षेत्र में अर्बनाइजेशन में जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, इसके लिए रूल्स और रैगुलेशंस बनने चाहिए कि तब तक नक्शा पास न किया जाये, जब तक हर मकान, हर बिल्डिंग में वे अपनी रेनवाटर हारवेस्टिंग की स्कीम न बनायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Resolution that has been moved by Shri Satpal Maharaj refers to three basic components, as far as I understand. First, he recognizes a serious crisis of availability of drinking water in various parts of the country. Second, the Centrally sponsored drinking water schemes like *Swajaldhara* and Accelerated Rural Water Supply Programmes are not being implemented and monitored properly. And the third is the suggestion that he wants to make, that this House urges upon the Government to formulate and implement a time bound comprehensive action plan at the national level to overcome the problem of drinking water. These are the three basic points which he has dealt upon and I will try to minimize my speech only to these three points.

As we are aware, historically, drinking water supply in rural areas in India has been outside the Government's purview or Government's sphere of influence. We had community managed open wells, private wells, ponds and small-scale irrigation reservoirs which have often been the main traditional source of rural drinking water. The first attempt -- the Government installed rural water supply schemes were implemented − was made in 1950s as a part of the Government policy to provide basic drinking water supply facilities to the rural population. Since then the involvement of the Government has increased with corresponding decrease in the role of communities in the rural water supply sector.

The Government of India's role in rural drinking water supply sector started in 1972-73 with the launch of the Accelerated Rural Water Supply Programme to assist different States in providing potable water to the rural population. This was the first stage and it happened from 1972 to 1986. The second generation programme started with the launching of Technology Mission. That was during Rajiv Gandhi's tenure in 1986 and later on during P.V. Narasimha Rao's tenure. It was called the National Drinking Water Mission. That was in 1991-92. These programmes from 1986 to 1996 made very little progress. The third generation programme - which started in 1999 through sector reform projects - involved the community in planning, implementation and management. It was later on called Swajaldhara in 2002. There was a change in policy there, change in the planning structure, change in the implementing sector, change in the sustainability of the programme.

I do not know which Minister is going to reply to this but we would have been happy if the Minister of Rural Development as well as the Minister of Urban Development would have been involved and would have participated in this discussion.

Already a huge investment of about Rs.72,600 crore has been made in rural water supply sector both by the Centre and the States since the beginning of the era of planned development in '50s up to 2009. A survey reveals that at any point of time there is a considerable gap between the assets that have been created and services that are available in rural population.

The major issue in the rural water system sector is the lack of sustainability of drinking water sources and systems. I will delve into that a little later. But the major question that confronts us today is, has the Government learnt from the past experience? Five to six years back, I had the privilege of visiting different sites. Satpal Maharajji hails from Haridwar and another learned Member also mentioned about Rishikesh. As members of the Public Accounts Committee we travelled from Rishikesh to Patna, sometimes by road and sometimes by train. We witnessed how Ganga was being systematically being killed. Killed by whom? By the people who reside on both banks of river Ganga. The two canals that come out to irrigate the fields keep the Ganga dry. Be it in Aligarh, be it in Kanpur, it is stinking. The money that was invested to treat the sewerage of different cities and towns on both sides of Ganga is not visible. It is the State Government's responsibility and that is how the Centre provides the money. Nothing much has happened.

It is only when we reached Allahabad, when river Yamuna touches river Ganga, that we find some water. People of Uttar

Pradesh are well aware of this. The river Ganga does not exist from Aligarh to Allahabad. It is just a sewerage stream. That is all. This is just an instance.

In every State, where a major city comes up or where township is growing or urban areas are growing, river becomes the sewerage line. In our Indian tradition, we pay respect to the river and we worship the river. Where is that tradition today? Where is that tradition today to protect the river water from contamination? Perhaps we have forgotten that tradition, that humility, that water is the panacea of human race. The health of any river is vital to the well-being of the country. Many well-funded river conservation programmes have been set up. So also, for the national rivers as it is declared, some money has been provided. In that, Mahanadhi also is included. But adequate fund needs to be provided. But money for only the first phase has gone; utilization has come for the last three years, but the rest of the money is yet to be provided there.

According to a report, compiled by 24 UN agencies, the world's population has grown to over six billion. Some countries have reached the limits of their resources. The report has estimated that due to climate change, half of world's population will be living in areas of high water stress by 2030, especially in Africa. Water scarcity in some arid and semi-arid places will displace between 24 million and 700 million people. This is very alarming.

There is a strong link between poverty and water resources − with the number of people living in less than 1.25 dollars a day approximately coinciding with the number of those without access to safe drinking water. This situation has a major impact on health, as almost 80 per cent of diseases in developing countries are associated with water, causing some three million early deaths. It is said that some 5000 children die everyday from diarrhoea and 10 per cent of all illnesses worldwide could be avoided by improving water supply, sanitation, hygiene and management of water resources.

It is now realized that the world is running out of fresh water; with every passing day, our demand for fresh water exceeds its availability. The social, political and economic impacts of water scarcity are rapidly becoming a destabilizing force. Unless we dramatically change our ways between one-half and two-third humanity will be living with severe fresh water shortage within the next 25 years.

Some of us believe that there is an infinite supply of fresh water on the planet. Many of us use water as if it will never run out. But this is not true. The available fresh water is less than one-half of one per cent of all the water that is on this Earth. In our country, the rain water storage is traditionally practised since ancient times; in our rural households, once in our backyard or in the front, it is a common site. The Government of India is propagating rain water harvesting, through different programmes of rural water supply. But are we aware that the ponds in home stead lands are shrinking day by day because of the pressure of population?

I have some suggestions to make, if the Minister can listen to them.

MR. CHAIRMAN : Please make them fast.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): I will make them very briefly.

As I had said, the major problem today is not creating the assets, but we have to sustain those assets so that they can provide service to the people. The major issue in the rural water sector is the lack of sustainability of drinking water sources and systems.

As a consequence, availability of drinking water both in terms of adequacy and quality on a sustainable basis has become a major challenge today. Does the Government have any programme other than delegating the responsibility to the State Government and to the Gram Panchayat, that is the ultimate elected body which we have in the villages? But, how do you repair? After this RWSS putting up different pipe water schemes in different villages now, which happened during Shri Ranghuvansh Prasad's tenure, when a major break down occurs who is going to repair it? We do not have a system and there is no expertise available neither in the villages nor in the block Panchayat headquarters. So, I would suggest that you need to have in place at district level a water security plan which should be hundred per cent grant-in-aid under sustainability programme in a revised guideline. You need to revise the guideline. This can be managed by the District Planning Board. What is happening today is, once the assets are created and handed over to the Gram Panchayats, the RWSS shifts its responsibility, takes its hands off. In this way, the programme will not sustain. The Government of India should develop the institutional mechanism through a regular grant-in-aid which would sustain the programme. But the question remains that we should learn from the experience.

With these words, I would say that this is high time that all of us, the sensible citizens of this country should protect water, use less water and also conserve water. Also, the assets that have been created should be sustained for our future generations.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, at the outset, I must appreciate the hon. Member, Shri Satpal Maharaj as he has taken the great initiative to bring forward this Resolution in this House. More often than not, here in this House we are discussing drought, flood or drinking water crisis on one pretext or the other.

Sir, first of all, we should appreciate that water is an elixir of all life. We should treat water as an asset. We should not treat water as a disposable article. Since the days of our civilization, human beings have been facing two kinds of problems; flood and drinking water. About 6000 years ago the human beings first discovered the hydro-technical installation to deal with the flood situation and also to procure drinking water for their survival. If we go through the history we will find that the oldest known cisterns were discovered in Palestine and Greece. The earliest dams to retain water were created in Java, Jordan about 3000 BC, Wadi Garawi in Egypt in 2600 BC. All the civilizations spanning from Niles to Tigris-Euphrates, Huang to Harappa Mohenjodaro flourished on the bank of rivers. But the fact is that in today's world we are gradually becoming vulnerable in the context of the availability of drinking water.

17.00 hrs.

It is often said that the last two world wars were fought on land but the third world war will be fought on water. We do not believe in the water war. We believe in water with peace. We require energy security for our country. We require internal security and national security for our country. In the same tune, we should also conceive water security for the present and for the coming generations because if we do not do any effective and fruitful measures today then our future generations will not pardon us.

As it is, it appears that we are sitting on the vast resources of water because three/fourth of our planet consists of water. But the grim reality is that 97.5 per cent of the water of this planet contains salty water and out of the remaining 2.5 per cent, 70 per cent is frozen in Antarctic and almost all of the remaining water is in the form of soil humidity and barely one per cent of fresh water is accessible to us.

India is a country which consists of 2.4 per cent of the global land, 16 per cent of the population and only four per cent of water resources.

17.02 hrs. (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

I would draw the attention of this House that in the year 1947 when we attained acquired our freedom, the *per capita* water availability was 6000 cubic metres. In the year 1997, the availability of water got decreased to 2300 cubic metres. The experts say that when the *per capita* water availability goes below 1700 cubic metres, it will be called water stress and when it will go below 1000 cubic metre, it will be termed as water scarcity. At the present juncture, 200 million population of our country is simply living in the water scarcity zone. This is the grim reality of our country.

I do not know whether this Ministry will singularly be able to deal with the water availability situation in our country because this is very much related to water resources also. So, my suggestion is that this Ministry in conjunction with the Planning Commission should formulate a long term action plan in order to ensure the water availability of our country because being a citizen of this country, everybody has the fundamental right to have fresh drinking water.

There are two components to ground water. One is static and the other is dynamic. The static region is an aquifer zone which does not need any replenishment. Water Resources available in this zone are of the order of 10812 billion cubic metres. The dynamic zone requires replenishment and the resources available in this zone are just 432 billion cubic metres. It is paradoxical to note that on one hand, in our country in the northern extreme there is a place called Cherrapunji which receives 14000 cm of rainfall and on the other hand, on another extreme we have a place called Jaisalmer which receives a rainfall of just 100 mm. Now, Cherrapujni is witnessing drought and Jaisalmer is witnessing flood. Such is the situation. But the fact remains that people of Jaisalmer were never forced to evacuate because of scarcity of water in that place. It is because they still follow the traditional way of conservation of rain water. Therefore, we have to ponder over how to sustain our water resources. We need more water because we are growing economy.

Sir, I would like to refer to three things here. First of all, we will have to educate ourselves on how to make use of water most prudently. It is because 67 per cent of irrigation water that is drawn from underground sources is wasted. Then, 20 per cent of total water is used for industrial purposes is also being wasted. What we need is more yield and less waste. We need to ensure that. We need to have water economy, irrigation economy because we never attach any worth to water either in agriculture or in industry and treat it just as a disposable article. Here I would like to refer to one quote from the famous book *`Arthasashtra'* by Chanakya. He said:

> "He should build the irrigation system with natural water sources, or with water to be brought in from elsewhere to others who are building these he should render it with lands roads trees and implements and also give it to the building of holy places and parks. If one does not participate in the joint building of an irrigation work his labourers and bullocks should be made to do his share of work and he should share the expenses but will not receive any benefits from it. The ownership of the fish, ducks and green vegetable in the irrigation works should go to the king."

Therefore, I would simply request the hon. Minister to initiate million well recharge programme under NREGA. We can easily put it into action. Water is an elixir of life. We should conserve water for our future generations.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Sir, I thank you for giving me this opportunity for participating in this discussion.

Day before yesterday, this august House discussed elaborately about drought and flood situation prevailing in the country. Today, we are discussing about drinking water problem. We are frequently using the proverb that prevention is better than cure. But we have not taken any precautionary measures to tackle the drinking water problem so far. Sometimes, heavy rain causes flood and havoc, and failure of rain causes drought. Indian agriculture itself is a gamble of monsoon. So, the Government of India has to come forward with a concrete solution to tackle the situation throughout the year. My revered leader, former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, during her regime, successfully implemented rain water harvest scheme with the active participation of people. Because of its implementation, the ground water level in all the areas of Tamil Nadu has risen to about ten to twenty feet. For consecutive three years, we managed the water problem in Tamil Nadu without any difficulty. Why not this scheme be adopted strictly and implemented throughout the country? It will solve the drinking water problem at least to some extent.

I am sorry to say that we lack sufficient knowledge on water management technique. If we adopt the water management technique wisely, we can overcome the problem successfully. As far as Tamil Nadu is concerned, we suffer more on account of drought because of the neighbouring States are not cooperative and unhelpful. We are being crushed in three corners, namely, non-release of water as per agreement by one State, objection to raise water level in the existing dam by another State, and unauthorised constructions across the inter-State river by yet another State. This is the situation now we are facing. I am sorry to say that the Central Government is a silent spectator to the problems of inter-State river water dispute. Even the Government of Tamil Nadu being a partner in the UPA Government does not want to raise this issue.

Taking this opportunity, I urge the Government to settle the Mullai Periyar issue, solve the Palar issue and finalise the Cauvery issue. These problems impede our progress. I hope that the aspirations of the people of Tamil Nadu will be met by the Central Government.

Another point is, since the industrial effluent sewage water is let out in the rivers, most of the rivers get polluted. In future, if this happens, we cannot get protected water even from the bore wells due to contamination. So, this issue has to be carefully dealt with.

It is the bounden duty of the Government, both the Central and the State Governments, to provide protected water to the citizens.

So, at least hereafter both the Central Government and the State Government should come forward to tackle the water problem, as requested by other colleagues also while mentioning the problems prevailing in their States. I hope the Central Government will take necessary steps to solve the water problem in our country.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): महोदय, आपने मुझे माननीय सतपाल महाराज द्वारा देश में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जल ही जीवन है और जल पर ही प्रकृति, मानव और कृषि निर्भर है। जल से ही पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं और पेड़ पौधों की वजह से ही मानसून आता है। मानसून से वर्षा होती है और उसी वर्षा से प्रकृति हरी भरी होती है। पहले पेयजल की उपलब्धता के तीन तरह के स्रोत होते थे पहला-कुएं, दूसरा-तालाब, तीसरा-नदियां। ग्रामीण अंचलों में पहले लोग कुएं खोद कर अपनी प्यास बुझाते थे और पानी की समस्या हल करते थे। आज स्थिति यह है कि ज्यों-ज्यों हम विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, त्यों-त्यों समस्याएं हमें घेरती जा रही हैं। गांव में कुओं का पानी संरक्षा और सुरक्षा के अभाव में पीने लायक नहीं रह गया है। उनका रखरखाव नहीं रखा जा सका, कीटनाशक दवाएं कुओं में नहीं डाली गईं और धीरे-धीरे उनका पानी पीने लायक नहीं रह गया। हमारी दूसरी व्यवस्था तालाब थी, जिसमें हम वर्षा के जल का संरक्षण करके पानी को सुरक्षित रख कर पीने के लिए उपयोग में लाते थे और कृषि के लिए भी उपयोग करते थे, अन्य समस्याओं का उससे समाधान करते थे, वे तालाब भी सिमटते गए। गांव के गलियारों में कस्बों में जहां तालाब खोदे जाते थे, वहां तालाब पाटने का काम शुरू हुआ। अब नरेगा के माध्यम से तालाब बनाने का काम शुरू तो हुआ है, लेकिन यह कहने में संकोच नहीं है कि वह केवल कागजों में है, जमीनीं तौर पर कुछ काम नहीं हुआ है।

हमारे जीवन का मूल स्रोत नदियां हुआ करती थीं, उनका मीठा जल, जिसे हम अमृत कहा करते थे, गंगा, यमुना जैसी तमाम नदियां, जो हमारे देश में प्रवाहित होती थीं, पहले वे पवित्र जल से भरी रहती थीं। लोग उनमें नहाते थे, पूजा करते थे और उस पानी से सिंचाई भी करते थे। आज कहने में संकोच नहीं है कि उन नदियों की व्यवस्था इतनी विकृत हो गई है, उनका पानी इतना गंदा हो गया है कि उसे पीना तो दूर, नहाना तो दूर, उस पानी को स्पर्श करने में भी कठिनाई होती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जल जो हमारे जीवन का प्रमुख स्रोत है, वही जल आज किस तरह से वर्षा के रूप में बहकर नष्ट होता जा रहा है। उसके लिए हम व्यवस्था नहीं करेंगे, डैम नहीं बनाएंगे, तालाब नहीं बनाएंगे, तो आने वाले दिनों में हम जल की ऐसी समस्या से ग्रसित होंगे, जिसका कोई निदान नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी ऐसे गांव हैं, परिवार हैं, जो पीने का पानी लेने के लिए मीलों दूर जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या जल की है। मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र भदोही में जाता हूं, ग्रामीण अंचलों में जाता हूं, जो पूर्वांचल का एरिया है, वहां कोई सड़क मांगने नहीं आता है, कोई स्कूल कालेज मांगने नहीं आता है, कोई अन्य समस्या लेकर भी नहीं आता है, अगर सौ लोग मिलने के लिए आते हैं तो नब्बे लोग ऐसे होते हैं, जो हैंड पम्प मांगते हैं, जो पेयजल की समस्या से प्रभावित होते हैं। आज यह स्थिति गांव में है और आने वाले दिनों में यह स्थिति और भी भयंकर होने वाली है। हमारी आबादी बढ़ रही है। हमारी जनसंख्या जयामिति विधि से बढ़ रही है और व्यवस्था को हम गणितीय विधि से बढ़ा रहे हैं। हमारी व्यवस्था एक, दो, तीन, चार की गिनती से चल रही है और हमारी आबादी दो दूनी चार, चार दूनी आठ की वृद्धि से बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पेयजल की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया तो अगर अगला कोई विश्व युद्ध हुआ, तो वह पेयजल के कारण होगा। आज हर व्यक्ति आने वाले भविष्य को देखकर परेशान है। कृषि के लिए किसान परेशान हैं, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी के लिए गांव का व्यक्ति परेशान है, क्योंकि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आज की स्थिति में जहां सारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं होते हुए भी हम कहते हैं कि हम ऐसे देश के निवासी हैं, जो धनी है।

लेकिन वहां निर्धन निवास करते हैं। हम धनी देश के लोग हैं, हमारे पास प्राकृतिक सम्पदाएं हैं, हमारे पास सारी सम्पत्तियां हैं, प्रकृति ने हमें दिल खोलकर दिया है लेकिन उसका सही दोहन, उसका उपयोग, उसकी व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जहां हम सारी सम्पत्तियों से परिपूर्ण हैं लेकिन अगर हम उसका उचित दोहन, उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमें घोर संकट का सामना करना पड़ेगा।

जब बरसात आती है, गांवों में हम लोग देखते हैं कि वह पानी स्वयं तो बहकर नदियों में चला जाता है लेकिन कटाव भी उत्पन्न करता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो हमारी कृषि योग्य भूमि है, उसे भी अपने साथ बहाकर ले जाता है। हमारी उर्वरक शक्ति भी समाप्त हो जाती है। हमारी कृषि भी उससे प्रभावित हो रही है। पानी तो समाप्त हो रहा है, कृषि भूमि भी समाप्त हो रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि बरसात के पानी को संचित करने के लिए तालाब बनाए जाएं, डैम बनाए जाएं। उससे पेयजल और खेती की समस्या का समाधान होगा।

हमारे देश में 83 प्रतिशत जल खेती और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। वर्षा का पानी बचाना होगा। देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो पीने के पानी के लिए तरसते हैं। हमारे क्षेत्र में भूगर्भ जमीन का पानी नीचे जा रहा है और वहां विषाक्त जल मिल रहा है। उसमें ऐसे तत्व मिल रहे हैं जिससे उस जल को पीने वाला व्यक्ति रोग से ग्रसित हो रहा है। गांवों ओर मोहल्लों से तालाब गायब हो रहे हैं। गांवों में बीमारियां केवल प्रदूषित जल को पीने की वजह से हो रही हैं। डायरिया, हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां केवल प्रदूषित जल को पीने की वजह से हो रही हैं। एक व्यक्ति को 3 लीटर पेयजल की जरूरत है और पशु को 50 लीटर पेयजल की जरूरत है लेकिन बोतल बंद पानी से किसी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। जैसे हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि बोतल का जल अमीर पी सकता है। लेकिन गांवों का गरीब जो झुग्गी में रहता है और जो पानी के लिए मीलों दूर जाता है, उसे बोतल का पानी नसीब नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि देश को बचाना है और खेती को बचाना है, हरियाली को बचाना है, सम्पन्नता को लाना है, गरीबी को समाप्त करना है तो वर्षा के पानी को संचित करना होगा, तालाब और डैम बनवाने होंगे और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : The time allotted for this Resolution is over. There are still ten Members yet to speak. If the House agrees, we can extend the time of the House by one more hour to discuss this Resolution.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): We will be sitting in the House up to six o' clock. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Yes, I am also telling the same thing. Then, if at all, the discussion on this Resolution is not completed today, we can take it up the next time. Today, of course, we will be sitting up to six o' clock.

...(*Interruptions*)

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): Sir, what about `Zero Hour'?

MR. CHAIRMAN: It will be taken up at six o' clock.

...(*Interruptions*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, मैं सतपाल महाराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई है। अभी मेरे पास में बैठे हुए मित्र कह रहे थे कि आप तो मेरठ के रहने वाले हैं, वहां तो पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। समस्या राजस्थान में है या देश के अन्य हिस्सों में है। मैं यही से यदि अपनी बात शुरु करूं तो गंगा और यमुना के बीच का जो भाग है, वह मेरठ कहलाता है। वहां भी पेयजल की समस्या बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही है। अभी हमारे माननीय सदस्य जी कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत बार नलों की मांग होती है। मेरे अपने क्षेत्र की स्थिति यह है कि पानी का स्तर इतना अधिक नीचे चला जा रहा है कि इंडिया मॉर्क 2 के पम्प उस पानी को खींचने की सामर्थ्य नहीं रखते। निरंतर उनको दुबारा बोरिंग किया जाए, ऐसी मांग होती रहती है। यह समस्या वैसे भी मुझे लगती है कि टुकड़ों के अंदर इसका हल नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि पानी प्रदूषित हो गया है। पानी के अंदर कारखानों का विषैला जल नदियों में छोड़ दिया जाता है जिससे वह प्रदूषित हो जाता है तो क्या हम उद्योग का विरोध करने वाले हैं? हम खेतों में पेस्टीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्षा का पानी इसे बहाकर ले जाता है, जल को प्रदूषित करता है। क्या हम पेस्टीसाइड्स का प्रयोग बंद करने वाले हैं? मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि जब तक समस्या के बारे में समग्रता से नहीं सोचा जाएगा तब तक उसका हल नहीं हो सकता। हमने पुरानी परंपराओं को भुलाया है और हमें उसका फल संभवतः मिला है। हमने जब से गंगा को मां न मानकर नदी मानना शुरू किया तब से हमने गंगा की शुद्धता का ध्यान रखना बंद कर दिया। मुझे अपने बचपन का स्मरण है कि कुआं पूजन के लिए गांव की महिलाएं जाती थी। इसका आशय यही था कि पानी का स्रोत पवित्र रहे और सम्पूर्ण जनता में सम्मान का भाव रहे। इस भाव के समाप्त होने के परिणामस्वरूप भी पानी की समस्या पैदा हुई है। मैं समझता हूं कि पिछले डेढ़-दो घंटे में माननीय सदस्यों ने इस पहलू को रखा है।

महोदय, मैं केवल एक विषय के बारे में चर्चा करके अपने विषय को पूर्ण करूंगा कि आज पीने के पानी का सबसे बड़ा स्रोत अंडरग्राउंड वाटर है। नदियों का पानी इस योग्य नहीं रह गया है कि उसे पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। मुझे इस बात की चिंता है कि अंडरग्राउंड वाटर को प्रदूषित किए जाने के प्रयास कारखाने या अन्य लोगों के द्वारा हो रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देता हूं, मेरठ जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में कमेले हैं। कमेलों में अनेक प्रकार का वेस्ट होता है जिसमें खून भी होता है। अंडरग्राउंड वाटर की शुद्ध जल से रिचार्जिंग नहीं हो रही है लेकिन उस खून के वेस्ट को सीधे बोर करके जल को प्रदूषित करने का काम निरंतर हो रहा है। मेरे क्षेत्र में तीन ब्लॉक्स हैं, खरखौदा ब्लाक है, रजपुरा ब्लाक है, वहां के जल के नमूनों में खून के हिस्से पाए गए हैं। इस प्रकार से अनेक कारखाने ऐसे हैं जो पानी को नाली के द्वारा बहाते नहीं हैं बल्कि 200-300 फीट बोर करके सारे पानी को डाल देते हैं जिससे पेयजल प्रदूषित होता जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रकार के प्रदूषण को कड़े कानून द्वारा प्रतिबंधित करें। यह बात हाथ से निकलती जा रही है, अगर हाथ से बात निकलने के बाद कुछ किया जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। इसे रोकने के लिए कड़े कानून बनाएं ताकि जो भी लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए कठोर कार्यवाही की जाए। इस प्रकार जल को प्रदूषित करने का प्रयास कहीं नहीं हो सकेगा। सदन में तालाब के बारे में बातें कहीं गई है, अन्य चीजों के बारे में बातें कही गई हैं। मैं अपने आप को इनके साथ सम्बद्ध करता हूं। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि भूमि के नीचे के जल को प्रदूषित होने से रोका जाए अन्यथा बात हमारे हाथ से निकल सकती है।

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच): माननीय सभापति महोदय, मुझे सतपाल महाराज द्वारा उठाए गए मुद्दे पानी की उपलब्धता और सुविधा के विषय पर बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इसी बात से शुरूआत करता हूं कि पहले गांव में कुआं होता था और आज भी कहीं-कहीं गांवों में कुएं का इस्तेमाल होता है। पिछड़े इलाके, जहां खास तौर से अनुसूचित जाति

और जनजाति के लोग बसे हैं, वहां कुएं का इस्तेमाल होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन इलाकों में जहां खास तौर से कुओं का इस्तेमाल होता है वहां के लिए आज भी स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन आज कुओं में क्या हो रहा है? इनसे तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं। इनमें मरे हुए जानवर गिर जाते हैं लेकिन इसी पानी को बिना जाने समझे लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे तमाम बीमारियां फैलती जा रही हैं। मैं बहराइच से सांसद चुनकर आया हूं। जहां ज्यादा जंगली इलाके हैं, सूखे जंगल हैं जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी लोग वहां रह रहे हैं। वहां लोग कुएं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जानवर मर कर कुएं में गिर जाते हैं और लोग उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं जिससे तमाम प्रकार की बीमारियां फैलती हैं।

इसके साथ ही मैं जल संसाधन मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि उनके लिए नलकूपों और हैंडपम्पों की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उन इलाकों के लिए एक एडीशनल और इम्पॉर्टेन्ट रेगुलेशन लाना चाहिए। अभी वहां सूखा पड़ा था, लेकिन अब उन इलाकों में बाढ़ आ गई। अभी हम लोग बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज तक पानी के लिए मर रहे थे। लेकिन अब वहां चारों तरफ पानी भर गया है। अभी सूखे से परेशान थे, लेकिन अब पानी के भरने से परेशान हैं। इसके कारण वहां तीन मौतें हो गईं। हमारे बहराइच में 53-54 मकान गिर गए। बहराइच में एक कतरनिया का इलाका है, जहां से पानी प्रवेश करता है। जब नेपाल का फाटक खुल जाता है तो वहां सब तरफ पानी भर जाता है। यह पानी इधर से सिद्धार्थनगर की तरफ चलता है और सिद्धार्थनगर से बहराइच की तरफ आता है और अंत में वह पानी राप्ती, घाघरा और कोसी नदी में मिल जाता है। जिसके कारण वहां बहुत नुकसान हो रहा है। एक तरफ हम सूखे से परेशान थे, अब हम बाढ़ से परेशान हैं। नेपाल ने पानी छोड़ा और पूरा पानी हिंदुस्तान में आ गया। मैं समझता हूं कि इसके लिए हिंदुस्तान की सरकार को नेपाल सरकार से बातचीत करनी चाहिए और इसका कोई न कोई विकल्प निकालना चाहिए। यदि इसका कोई विकल्प नहीं निकाला गया तो ये चीजें हमेशा होती रहेंगी। आज जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें हमें पानी इकट्ठा करना चाहिए और पानी इकट्ठा करने के बाद वहां एक हाइड्रो स्टेशन खोल देना चाहिए। इससे वहां बिजली पैदा होगी और वह बिजली पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को मिलेगी। हमारे प्रदेश से लगे इलाके दिल्ली में ज्यादा बिजली मिलती है। यदि वहां बिजली पैदा होती तो उन इलाकों में कोई परेशानी नहीं होती।

दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो जंगलात का इलाका है, आज वहां भी बरसात कम होनी शुरू हो गई है। पहले क्या होता था, वहां जैसे ही बादल आते थे, बारिश हो जाती थी। लेकिन अब वे भी सूखते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि वहां पानी का स्तर बिल्कुल नीचे जा चुका है। यदि इसी तरह पानी का स्तर नीचे गिरता गया तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में यह बहुत बड़ी परेशानी के रूप में सामने आयेगा। अभी सदन में चर्चा हो रही थी कि पानी की कमी की वजह से अगला विश्व युद्ध होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको पानी की उपयोगिता के बारे में बताना चाहता हूं। आज पानी की उपयोगिता बहुत अधिक है। It is very important for this country and also for every country. I worked in the Armed Forces and I have seen all the areas. मैं आपको फोर्स के बारे में बताता हूं, I do not want to go into details. लेकिन हमें वहां तीन लीटर पानी तीन-तीन दिनों तक इस्तेमाल करना पड़ता था। फोर्स में रहने के कारण मुझसे कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा है, जहां मैं नहीं गया हूं। चाहे सिक्किम की पहाड़ी हो, चाहे असम की पहाड़ी हो, चाहे उत्तरांचल की पहाड़ियां हों, मैं सभी पहाड़ियों पर घूमा हूं। मैंने फिजीकली इन इलाकों को देखा है। इन सब एरियाज में हर तरह की परेशानी है। खासकर उन इलाकों में, जहां एस.टी. के लोग रहते हैं। यह हो सकता है कि इस सदन के लोग किसी बॉर्डर पर न गये हो, लेकिन ऐसा कोई बॉर्डर नहीं होगा कि जिस बॉर्डर पर मैंने जाकर काम न किया हो।

महोदय, इन्हीं बातों के साथ अंत में यह कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि देश में शुद्ध जल की उपलब्धता की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं सतपाल महाराज द्वारा प्रस्तुत प्राइवेट मैम्बर बिल का समर्थन करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, श्री सतपाल महाराज जी ने बड़ा ही सामयिक और प्रासंगिक विषय पीने के पानी की समस्या, जो उनके अपने इलाके और देश भर में उत्पन्न हो रही है, इस समस्या पर उन्होंने संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है। इससे सभी माननीय सदस्यों और सदन को फायदा हो रहा है, चूंकि अपनी-अपनी समस्या लोग यहां बता रहे हैं। वैसे देखें तो "क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच रचित अति अधम शरीरा"। सृष्टि की रचना में पांच चीजों में एक पानी है और उस रचना में चार हिस्से में तीन हिस्से पानी है और एक हिस्सा जमीन है। लेकिन जानकार लोग बताते हैं कि पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा। अब भविष्य में विश्व युद्ध होगा या नहीं, लेकिन मैं सदन में कभी-कभी देखता हूं कि यहां पानी के लिए युद्ध जरूर हो जायेगा। कावेरी का इश्यु आता है तो तमिलनाडु और कर्नाटक के माननीय सदस्य ख़ड़े हो जाते हैं। नर्मदा का इश्यु आता है तो उसमें भी दो राज्यों के माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं। इसलिए पानी की परिस्थिति बहुत कठिन है, ऐसा मैं महसूस करता हूं।

देश के विभिन्न राज्यों के बीच में भारी मतभेद और झगड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ट्रिब्यूनल बने हैं । जब मैं सदन मे देखता हूं तो भयभीत हो जाता हूं कि पानी की समस्या के लिये विश्वयुद्ध होने वाला है। इसमें हम लोगों को एक काम करना है। लोगों की मान्यता है कि धरती के अंदर पानी का स्रोत खत्म होने वाला नहीं है और अशुद्ध भी नहीं है। लेकिन यह गलत है क्योंकि पानी घट रहा है। माननीय सदस्य श्री अग्रवाल जी कह रहे थे कि यह पानी दूषित होने की भी संभावना है। पहाड़ से ठोस रूप में बर्फ वाला पानी ग्लेशियर्स का आता है, अंटार्कटिका में जमा हुआ है। एक बड़ा वाला पानी और दूसरा सरफेस वाला पानी जो ग्राउंड वाटर कहलाता है। समुद्र का 97 प्रतिशत पानी खारा होता है, वह पीने लायक नहीं है। इसीलिये इतना ही पानी है कि जो ईरिगेशन और उद्योग में जाता है तो पीने के लिये 2 फीसदी पानी बचता है।

सभापति महोदय, मैं देखता हूं कि प्रथम पंचवर्षिय योजना से लेकर आज तक पानी के लिये 62 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो नाममात्र का पैसा खर्च किया गया लेकिन जैसे जैसे योजना का आकार बढ़ता गया और विशेषज्ञों और जानकारों ने जन समस्याओं की तरफ गांवों की ओर ध्यान दिलाया तो पैसा ज्यादा खर्च किया जाने लगा। लेकिन उतरार्द्ध में पीने के पानी की समस्या पर जोर दिया गया है। अभी भी हिन्दुस्तान में तीन तरह के पानी की समस्या है - पानी की उपलब्धता, सस्टेनेब्लिटी ऑफ वाटर और क्वालिटी ऑफ वाटर। तीनों तरह की समस्यायें अभी भी बनी हुई हैं लेकिन माननीय सदस्य ने हिमालय, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी का जिक्र किया है तो वह इलाका बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि वहां क्वालिटी ऑफ वाटर है। यदि उत्तराखंड में पानी की उपलब्धता की समस्या हो गई तो गुणवत्ता की समस्या आयेगी। वहां पानी की उपलब्धता की समस्या है। फिर सस्टेनेब्लिटी ऑफ वाटर की प्राब्लम है। इसलिये, इस पर भारत सरकार ने जोर दिया है। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत यह राज्य का दायित्व है कि वह पेय जल की समस्या को देखेगी। भारत सरकार ने प्रयास किया है और सहायता दी है। गत चार वर्षों के अंदर एक लाख 74 हजार करोड़ रुपये खर्च करना है , उसमें पानी एक हिस्सा है। बाकी हिस्सा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का है, रूरल हाऊसिंग का है, बिजली लगानी है, सिंचाई करनी है लेकिन उसमें पेय जल के लिये भी एक हिस्सा है। इसलिये मैं महसूस करता हूं कि इस मामले में भारत सरकार का जोर है। अगर हम जनता को शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं कराते तो इसे क्रिमीनल नैग्लीजैंस से कम नहीं कहा जा सकता है। आज हम लोगों को जानकारी नहीं है ।

सभापति महोदय, जानकार बताते हैं कि आधे से ज्यादा बीमारियां गावों में अशुद्ध जल पीने से गरीब लोगों को होती हैं। इसलिये गांव के सब से ज्यादा लोगों की सहायता यह होगी कि उन्हें पीने का शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाये। हिन्दुस्तान में लगभग पांच लाख लोग डायहरिया से मरते हैं क्योंकि उन लोगों को पीने के लिये शुद्ध जल नहीं मिलता है। इसलिये शुद्ध पानी का प्रबंध होना चाहिये। हमारे पास शुद्ध पानी के लिये क्या उपाय हैं? माननीय सदस्यों ने इस पर गम्भीरता से जिक किया है। इसलिये वाटर कंजर्वेशन को टॉप प्रायरिटी दी जानी चाहिये। वर्षा से शुद्ध जल दुनिया में कहीं नहीं है। एच2ओ पानी, हाईड्रोजन का दो हिस्सा, आक्सीजन का एक हिस्सा। लेकिन वर्षा का पानी, शुद्ध पानी है, उसमें कोई दूषित पानी होने की प्राब्लम नहीं है। इसलिये रेनवाटर हारवैस्टिंग, रूफ टाप वाटर हार्वैस्टिंग और फिर उसका रीचार्ज धरती के अंदर जब वर्षा होती थी।

पहले जो वर्षा होती थी वह एक तिहाई पानी धरती के अंदर सोखती थी। जैसे ही सड़कें और मकान बने तो पानी को रूकने की जगह नहीं मिली और सब पानी समुंद्र में बहकर जा रहा है इसलिए ग्राउंड री-चार्ज करने की योजना बननी चाहिए। हालांकि वाटर कंजरवेशन को रोजगार गारंटी कार्यक्रम में टॉप प्रायोरिटी दी गयी है, कि वाटर कंजेरवेशन होगा, ताल-तलैया होंगी।

महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने इलाके में पीने के पानी की समस्या पर बातें की हैं, उसमें माननीय सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए। श्री जगदीश शर्मा जी भाषण कर रहे थे कि पानी पीने की समस्या है। आज सात सौ करोड़ रूपए बिहार के खजाने मे पड़े हुए हैं, कई वर्षों से ये खर्च क्यो नहीं हो रहे हैं? माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं-नहीं, केवल जानकारी ही नहीं, उनकी इसमें भागीदारी होनी चाहिए।

महोदय, पैसे वहां पड़े हुए हैं और यहां हम पीने के पानी की समस्या पर चिंता और बहस करते हैं। सभी लोग गांव में जाते हैं, वहां मुसलमान बहुत कम हैं, उनकी मांग है कि हमें अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति में शामिल करो। आप उस इलाके में जाइए,जहां गरीब आदमी बसता है। वहां पानी पीने का संकट है, वे दूर से पानी लाते हैं और वहां पीने के पानी के लिए कोई उपाय नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि सारे पैसे खर्च हों...(<u>व्यवधान</u>) हो भी रहे हैं, लेकिन समस्याएं बनी हुई हैं। पांच हजार नौ सौ बीस हैबिटेशंस में 10 लीटर प्रति व्यक्ति से कम पानी है, हुकुम देव नारायण यादव जी भाषण कर रहे थे। शहर में 200 लीटर प्रति व्यक्ति और गांव में 40 लीटर प्रति व्यक्ति ही पानी की उपलब्धता अभी तक नहीं हो पायी है। उसी में नहाना, उसी में खाना और उसी में पशु-पक्षी, इसलिए उस पर माननीय सदस्यों की जानकारी और उनकी भागीदारी कराने की जरूरत है।...(<u>व्यवधान</u>) यह भी जरूरत है कि कैसे उसका खर्च हो। पानी की समस्या को टॉप प्रोयोरिटी में रखना होगा और उसका प्रमुख अंग भारत निर्माण होना चाहिए। माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी और भागीदारी अवश्य होनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN : You have made your point; it is well taken.

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record further.

*(Interruptions) â€¦ **

* Not recorded.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जो विषय माननीय सतपाल महाराज जी के द्वारा लाया गया है, उसका हम समर्थन करते हैं। इस विषय पर जिन्हें अपने विचार रखने का मौका मिला, उस विषय से हम अपने आप को जोड़ते हैं और जो विषय छूटा हुआ है उसकी और मैं मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।

महोदय, आज का दिन अच्छा भी कहा जाएगा और दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जाएगा क्योंकि आजादी मिले हुए 62 वर्षों के बाद भी आज हम इस लोकसभा, जो सबसे बड़ी पंचायत है में पीने के पानी के संकट के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, आज चिंता इस विषय की होनी चाहिए कि जो हमारी पुरानी योजनाएं हैं, चाहे वे केंद्र सरकार की जिला-पूर्ति योजनाएं हों या राज्य सरकार की योजनाएं हों, वे योजनाएं पूर्ण रूप से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हम उन्हें कैसे व्यवस्थित करें, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है ताकि वहां की समस्याओं का निदान तत्काल किया जा सके। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, हम झारखंड राज्य से आते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पलामू परिमंडल और पूरे झारखंड प्रदेश में पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था का माध्यम केवल नदियां हैं।

दामोदर नदी, जो कि वहां की जीवन रेखा है, वह आज प्रदूषित हो गई है। यह नदी दुनिया की तीसरी सबसे प्रदूषित नदी है। यह नदी सीधे समुद्र में जाकर मिलती है। उसको कैसे ठीक किया जाए? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि जलापूर्ति की वर्तमान योजनाओं को कार्यान्वित करने में सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि वहां की जो समस्या है, उसका निष्पादन हो सके।

महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोग जिस राज्य से आते हैं, वहां 15 दिन पहले महंगाई के नाम पर उग्रवादियों द्वारा झारखण्ड बंद किया गया था। वहां एक दुकान नहीं खुली और एक भी वाहन नहीं चला। इसका मतलब यह हुआ कि पेयजल पर पूरे हिन्दुस्तान में अथवा खासकर झारखण्ड में जहां के 24 में 22 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं, आज यदि घोषणा हो जाए कि झारखण्ड एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा तो हम लोग एक सप्ताह के लिए घरों में बंद रहेंगे। आपसे मेरा निवेदन होगा कि पेयजल का परमानेन्ट सोल्यूशन होना चाहिए ताकि यहां के लोगों को लाभ मिल सके और सिंचाई की भी व्यवस्था हो सके। आज हम इस विषय को रख रहे हैं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Mr. Chairman, Sir, I welcome the Resolution brought forward by Shri Satpal Maharaj.

Water is a must. We have to preserve and conserve water; also we have to use water in a proper way. A lot of rivers are flowing from Karnataka, Kerala and Andhra Pradesh, and they are coming inside the territory of Tamil Nadu.

Cauvery river is passing through a stretch of 90 kilometres only in Karnataka whereas it is passing through a stretch of 500 and odd kilometres in Tamil Nadu. Tamil Nadu State could not put up a check dam. If we put up a check dam, immediately it is objected to by the Karnataka State people.

For preserving water, a common law should be enacted by the Central Government; or else, all the river waters should be nationalized in the larger interest of the people of India.

Karnataka State has constructed five huge dams, and so, water is not coming to Tamil Nadu. During the rainy season also, our dam is not full. The full level of our dam is 150 feet but we have water up to 90 feet only. So, I would request the Central Government to enact a common law for preserving water. If we nationalize the waterways, then good things will happen.

There is a beer factory − I do not want to mention the name − in the Chennai city. Earlier I was a Member belonging to that Assembly constituency. At that time, one person in my constituency had given me a report, in which he had said that the put the water coming out from the beer inside the well. With the result, those who are residing in the adjoining areas of about five to six kilometres and who are drinking water through pump or well, their eyesight are getting affected. Most of the persons who are below 40 years in that area are wearing spectacles; a minimum of 100 children in that constituency are dying in a year due to diarhoea or some other disease. The teeth of those who consume the contaminated water are becoming yellow. It is because the water in that area has the highest fluoride content.

So, if we do not conserve water and if we do not treat it properly, a lot many disease would be coming.

About the bore-well, previously in my village, within 100 feet, we were getting good water. Then, the water level went to 150 feet. Now, we have to go from 500 feet to 1,000 feet to dig a bore-well. In Madurai, in my Constituency, they are taking water directly from the river and supplying it to the people. It is so hazardous and harmful. Water is coming in yellow colour during rainy time. It is not even treated in a proper way. My suggestion is that before supplying water to the general public, it should be treated properly.

The State of Andhra Pradesh is constructing a dam in Palaru. The Central Government should give suitable instructions to Palaru in this regard. Same is the case in Kusathaliaru and Cauveri rivers. So, we need to put check dams in every two kilometres, at least, to the height of two to three metres. Then only, we would be able to preserve water; and the ground water level would also increase. This way, we can supply good water to the people.

With these few words, I conclude and support this Resolution.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

Now, Shri Bishnu Pada Ray. You may make your points and conclude your speech within three minutes because we are winding up at 6 o' clock and there is still one more Member to speak.

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): Mr. Chairman, Sir, I come from Andaman and Nicobar Islands. अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और नार्थ-ईस्ट, जहां से कुमारी अगाथा संगमा जी आई हैं, वह हाई रेन फॉल एरिया है, लेकिन वहां पीने के पानी की सभी लोगों को तकलीफ है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भी पीने के पानी की तकलीफ है।

सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 62 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, फिर लोगों को पीने का पानी क्यों नहीं मिला? मैं वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में भी सांसद था। भारत सरकार मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को मिसलीड करता है। मैंने पीने के पानी के लिए अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह का प्रश्न किया तो मुझे पार्लियामेंट के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालय से यह जवाब मिला कि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में सब लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। फिजिकल टारगेट एक चीज है और फाइनेंशियल एचीवमेंट अलग चीज है। यह पीने के पानी के नाम पर बड़ा घोटाला और डकैती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, यहां मंत्रालय के बड़े सीनियर आफिसर्स गैलेरी में मौजूद हैं। कुछ एनजीओज़ और आफिसर्स भी चिन्ता करते होंगे, जिनके दिमाग में नये-नये विचार आते होंगे। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में पांच हजार वाटर हारवेस्टिंग के टैंक बनाए गए। वहां पूरा वर्षा का पानी गिरता है। वहां पाइप लगाया, टैंक बनाया, पांच हजार पीने के पानी के टैंक सिर्फ मोन्युमेंट बन कर रह गए हैं, उसमें बूंद मात्र पानी नहीं है। वह मच्छर पलने की जगह बन गई है। पांच हजार टैंक के लिए कितना करोड़ रुपया गया? आज 62 साल बाद भी पीने के पानी की चर्चा पार्लियामेंट में होती है। यहां कुमारी अगाथा संगमा जी बैठी हैं, ये जवान हैं, बुद्धिमान हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि पीने के पानी को लेकर पार्लियामेंट में जो मिसलीड किया गया, अंडमान-निकोबार को किया, उसकी छानबीन करें।

सभापति महोदय, मैं पोर्ट ब्लेयर पीने के पानी के बारे में कहना चाहता हूं, बाद में मैं सजेशन दूंगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर में एक ही म्युनिसिपल काउंसिल है, मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार पोर्ट ब्लेयर में आएं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Still one more speaker is there to speak. He will take another five minutes. I have to give him time also.

श्री विÂष्णु पद राय : सभापति महोदय, आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पीने का पानी नहीं है। इसलिए मैं सुश्री संगमा जी को पानी के बारे में कुछ सजैश्चन देना चाहता हूं। भारत में जो रैपुटेटेड एन.जी.ओज. हैं, उनका एक डेलीगेशन स्टेट में भेजा जाए। वह डैलीगेशन केवल स्टेट हैडक्वार्टर पर ही न जाए, बल्कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज लैवल पर जाकर जांच करे और रिपोर्ट दे कि पीने के पानी के लिए कितना रुपया दिया गया था, कितना रुपया खर्च किया गया और फिजीकली कितना एचीवमेंट हुआ और आज पानी की तकलीफ कहां-कहां है और पानी का सोर्स कहां-कहां है। नॉर्थ-ईस्ट और अंडमान, जोन-5 में हैं। वहां पहले जो वाटर के लिए टैंक बना, वह अगले सुनामी के समय क्रैक होगा और इस एरिया के लिए खतरा बनेगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि उस एरिया के लिए ऐसा प्लान बनाएं, जिससे पीने का पानी वहां के लोगों को मिल सके। मैं 'नरेगा' के बारे में कहना चाहता हूं कि इस स्कीम में स्किल्ड का कंपोनेंट नहीं आने के कारण वह योजना ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो एम.पीज. पार्लियामेंट्री कमेटी में भाग लेते हैं। उन्हें एक टास्क दिया जाए कि वे कुछ स्टेट्स के कुछ जिलों को चुन ले और वहां पीने के पानी की समस्या का अध्ययन करें। मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट-वाइज वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बनाए जाएं। यहां मिनिस्ट्री के ऑफीसर्स भी बैठें हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाए कि वे इस समस्या के समाधान के लिए दौरा और मीटिंग करें, तब पानी की समस्या दूर होगी, नहीं तो भारत की संसद में इस बारे में परमानेंट रूप से चर्चा होती ही रहेगी।

MR. CHAIRMAN: Shri Jagdambika Pal, you take five minutes' time. At 6 o' clock, you have to wind up. Then only we can finish.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विÂाय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। पानी के महत्व के बारे में माननीय सदस्यों ने जो कहा है, मैं उनकी भावनाओं से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मैं पूरी दुनियां में पानी के बढ़ते हुए संकट की ओर सम्मानित सदन और सरकार का ध्यान आकृÂट करना चाहता हूं। इस देश में, पहले पानी की कमी राजस्थान में हुआ करती थी। राजस्थान के लोग गर्मियों में दूसरे राज्यों को पलायन करते थे। आज राजस्थान जैसी स्थिति दूसरे राज्यों की हो गई, यहां तक कि हिमालय में और उत्तराखंड में भी पानी के संकट की तरफ माननीय सतपाल महाराज ने ध्यान आकृÂट किया है और एक संकल्प लेकर आए हैं। जब दुनिया में पानी का संकट बढ़ रहा है और यह कहा गया है कि वÂाऩ 2025 तक 1.8 अरब लोगों के लिए पानी का संकट हो जाएगा, तो इस पर निश्चित रूप से पूरे सम्मानित सदन को गंभीर चिन्ता करनी होगी।

महोदय, आज दुनिया में पानी की उपलब्धता कितनी है, मैं इस बारे में बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया में 97.5 परसेंट पानी नमकीन यानी साल्टेड है, जो पीने योग्य नहीं है। केवल 2.5 परसेंट पानी पीने योग्य है। अगर आज 25 लीटर पानी में एक बूंद भी तेल गिर जाए, तो वह पानी खराब हो जाता है। आज जो पानी की स्थिति है, वह मैं बताना चाहता हूं कि सामान्य देशों में उपलब्ध कुल पानी का 70 प्रतिशत पानी खेती के लिए उपयोग होता है, 22 प्रतिशत पानी उद्योग के लिए और 8 प्रतिशत पानी केवल डॉमैस्टिक कार्यों के लिए यूज होता है। जो गरीब, लो और मिडल इन्कम वाले देश हैं, उनमें 82 प्रतिशत खेती, 10 प्रतिशत उद्योग और 8 प्रतिशत घरों के इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जाता है। जो विकसित देश हैं वहां केवल 30 प्रतिशत पानी खेती, 50 प्रतिशत उद्योग और 11 प्रतिशत घरों के लिए यूज हो रहा है। आज यदि व्यक्ति को खाना न मिले, तो वह एक महीने भी जीवित रह सकता है, लेकिन पानी न मिले, तो वह 5 या 7 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है।

महोदय, मैं वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकरÂिात करना चाहता हं जिसके

अनुसार 6000 बच्चे वॉटर रिलेटेड बीमारियों से मर रहे हैं। अगर उन 6000 बच्चों को जीवन मिले, तो वे आई.टी. या विज्ञान के क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं। आज स्थिति यह है कि हम 5 मिनट के शॉवर में हम 94.52 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं। फ्लश के लिए 7,6 लीटर से लेकर 26.5 लीटर पानी खर्च कर देते हैं। हाथ धोने और दांत साफ करने के लिए 7.6 लीटर से 2 गैलन पानी खर्च कर देते हैं, जबकि हमारे देश की रिपोर्ट यह है कि 21 परसेंट लोग वाटर रिलेटेड बीमारियों से परेशान हैं। 1999 की बात मैं कह रहा हूं कि केवल डायरिया से 7 लाख लोग मरे थे। मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूं। मैं केवल उन बिन्दुओं का उल्लेख कर रहा हूं जो गम्भीर हैं। 7 लाख लोग मर गए, यानी औसतन 1600 लोग प्रति दिन। इसमें जो पांच साल के बच्चे थे वे बी मर गए। मैं निश्चित रूप से इस सरकार को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उसने राÂट्रीय जल नीति वÂान 2002 में घोÂित की।

18.00 hrs.

उस 2002 की राष्ट्रीय जल नीति से मैं तो कहूंगा कि एक कदम आगे यह जल का विषय राज्यों का विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी आज चिन्ता है। जो लोग गंगा की बात करते थे, गौमाता की बात करते थे, उन्हें इसकी चिन्ता नहीं हुई। अगर आज गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर देने का काम किया है तो कांग्रेस-यू.पी.ए. की सरकार ने घोषित करने का काम किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो जल का भयावह संकट आने वाला है, उस स्थिति को देखते हुए आज 2001 की जनगणना के अनुसार अगर 1027 मिलियन जनसंख्या के आधार पर अगर प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता देखी जाये तो 1820 घन मीटर बैठती है ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please wind up in one minute.

श्री जगदम्बिका पाल : हमारी स्पीच कंटीन्यू रखेंगे या कन्क्लूड करेंगे?

SHRI B. MAHTAB : Mr. Chairman, Sir, I have one suggestion to make. I think this Session is going to be concluded on 7th August.

MR. CHAIRMAN : 7th August, Friday, is there. Let him finish now.

श्री जगदम्बिका पाल : तो आज जो पानी का संकट है, इस पर हमें निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए शुद्ध पेयजल की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति कैसे करें। निश्चित तौर से आज पानी का वाटर स्टेटा नीचे जा रहा है। आज कहीं हैंडपम्प काम नहीं आ रहे हैं। अब तो जो इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प भी गांवों में लग रहे थे, उनका पानी भी गर्मियों में नीचे चला जाता है। एक दिन मैंने कहा था कि हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जो टयूबवैल्स हैं, उनमें पानी नीचे जा रहा है। अभी हमारे राजेन्द्र अग्रवाल जी ने भी कहा कि आज टयूबवैल्स भी बेकार हो रहे हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसके अनुपात में पानी का ट्रीटमेंट हमको करना होगा। उस पर सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा और जो 97.5 परसेंट साल्टेड वाटर है, समुद्री जल है, उसको भी रीसाइकिल करना होगा। अगर अन्तरिक्ष यात्री स्पेस में जाकर अपनी सोइल से पीने के पानी को रीसाइकिल कर सकते हैं, जिस पानी को पिया नहीं जा सकता है तो निश्चित तौर से जो साल्टेड वाटर या समुद्री पानी है, उसको भी रीसाइकिल किया जा सकता है। वाटर हारवैस्टिंग की बात हमारे बहुत से साथियों ने कही है।

समय की कमी है, इसलिए मैं यह सुझाव देते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Thank you. We will now take up the 'Zero hour' matters. Dr. Kirit Premjibhai Solanki to speak for three minutes.